Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-17, अंक-10 16-31 मई, 2022 (पाक्षिक) ₹20

'हमें अपनी विचारधारा को यशस्वी बनाकर देश को निरंतर आगे बढ़ाना है'

प्रधानमंत्री की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस यात्रा

व्यापार, निवेश और हरित ऊर्जा को बढ़ावा

तेलंगाना में कमल का खिलना तय

ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट

भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध लड़ने को प्रतिबद्ध भाजपा

वडोदरा (गुजरात) में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत करते भाजपा कार्यकर्तागण

कोझीकोड (केरल) आगमन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत

हैदराबाद आगमन पर तेलंगाना भाजपा द्वारा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में एक विशाल जनसभा में जनाभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

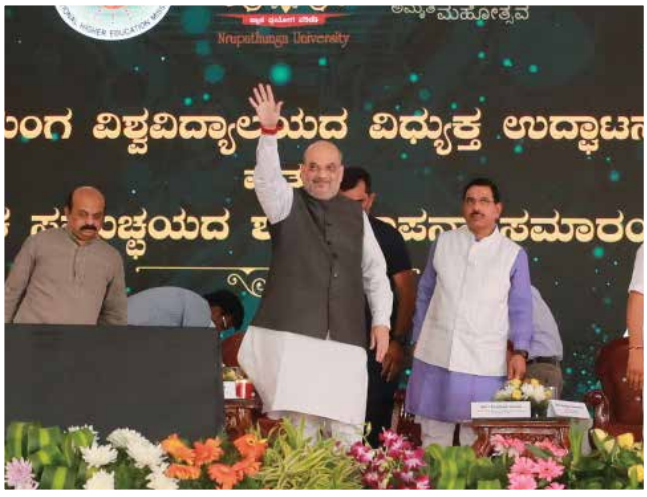

बेल्लारी (कर्नाटक) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

हैदराबाद (तेलंगाना) में 12 राष्ट्रीय राजमार्गों और 7 सीआरआईएफ परियोजनाओं का शुभारंभ करते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी व अन्य

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

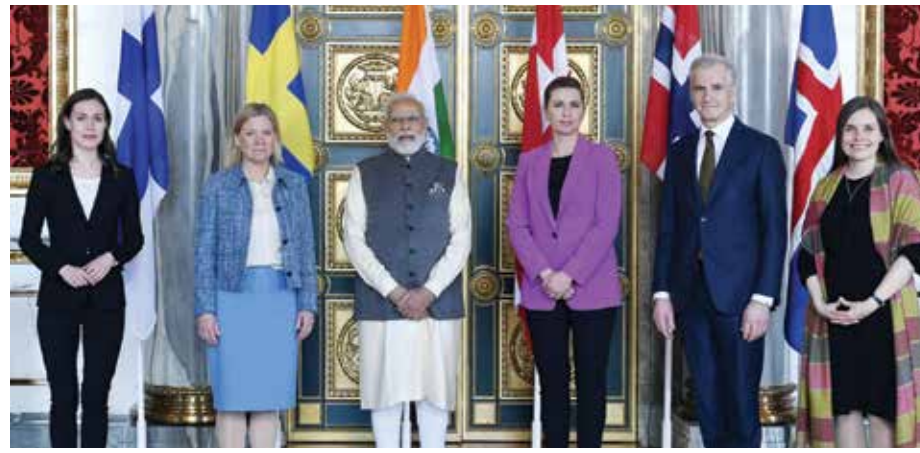

06 व्यापार, निवेश और नयी हरित साझेदारियों को मिला बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2-4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की सफल यात्रा की। इस तीन दिवसीय यात्रा के मध्य श्री मोदी ने व्यापार, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के...

10 तेलंगाना में कमल का खिलना तय है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 5 मई, 2022 को तेलंगाना के...

12 'हमें अपनी विचारधारा को यशस्वी बनाकर देश को निरंतर आगे बढ़ाना है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 अप्रैल, 2022 को गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल...

14 जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध लड़ने को प्रतिबद्ध भाजपा: अमित शाह

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 05 मई, 2022 को...

26 'आत्मनिर्भर भारत' हमारा रास्ता भी है और संकल्प भी: नरेन्द्र मोदी

गत छह मई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के 'जीतो...

वैचारिकी

हमारा हित / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 20

श्रद्धांजलि

कुशल राजनेता के. जना कृष्णमूर्ति 22

साक्षात्कार

देश भर के किसान मोदीजी के साथ हैं: **राजकुमार चाहर** 28

लेख

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण नीति निर्धारक के रूप में उभरा / **विकास आनन्द** 30

अन्य

'वाम मोर्चा सरकार केरल में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है' 16

अप्रैल, 2022 में अब तक का सर्वाधिक 'सकल जीएसटी राजस्व संग्रह' 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा 17

भारत के सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 254.4 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया 18

भारत में बना 100वां यूनिकॉर्न 19

असम में कैंसर अस्पतालों से पूर्वोत्तर के साथ-साथ दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य सेवा की क्षमता में वृद्धि होगी: नरेन्द्र मोदी 23

'हर छोटा एवं बड़ा व्यवसाय राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे रहा है' 24

'हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का माध्यम संस्कृत ही है' 25

भारत ने अपनी 85 प्रतिशत पात्र आबादी का कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण किया 26

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले 32

मन की बात 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ. प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमें न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।

जगत प्रकाश नड्डा

भारत अब निर्यात करने का सबसे बड़ा हब बन रहा है, 400 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। पहले भारत इम्पोर्ट करता था, मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है।

अमित शाह

2014 से पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन देखकर काफी निराशा होती थी। मोदीजी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया, फ़िट इंडिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसी कई पहल की हैं, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।

राजनाथ सिंह

मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने वाले 'वीर शिरोमणि' महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें स्मरण एवं नमन करता हूं। अपने साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ा और सबका विश्वास प्राप्त किया। महाराणा प्रताप का जीवन और संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।

बी.एल. संतोष

मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 25 में से 12 सीटें जीतकर मिजोरम भाजपा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ—सबका विश्वास' दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उत्तर पूर्व में अपना विस्तार किया है। मिजोरम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश इकाई को बधाई।

नितिन गडकरी

'उत्कर्ष समारोह' कार्यक्रम के दौरान गुजरात में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में से एक अयूब पटेल जी से बात करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पटेलजी की बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के बारे में सुनकर भावुक हो गए। यह प्रधानमंत्रीजी की देशवासियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

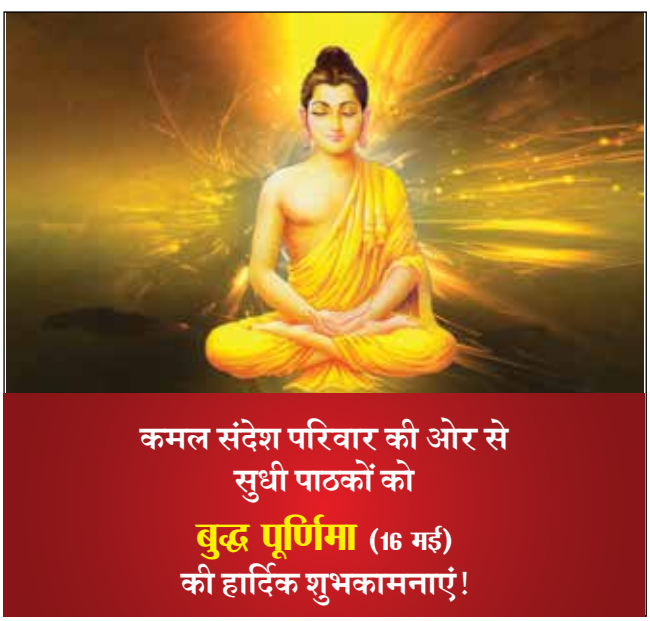

संपादकीय

प्रधानमंत्री की सफल यूरोपीय यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाल के जर्मनी, डेनमार्क एवं फ्रांस की यात्रा से संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। साथ ही, इस यात्रा से भारत के नए क्षेत्रों में भागीदारी के लिए सक्रिय प्रयासों का परिणाम भी सामने आया। भारत की विदेश नीति में प्रवाहित होती यह नई ऊर्जा देश के वैश्विक दायित्वों के निर्वहन करने की तत्परता एवं विभिन्न देशों के साथ बहुस्तरीय भागीदारी में परिलक्षित हो रही है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उदय हो रहे एक नए भारत का उद्घोष है जो 'शीत युद्ध' के साये से बाहर निकल चुका है और बिना किसी हिचक के हर देश से सकारात्मक संबंध बनाने को प्रयासरत है। यूरोपीय देशों के साथ भागीदारी से आने वाले दिनों में भारत के लिए संभावनाओं के अनेक द्वार खुलेंगे तथा भागीदारी करने वाले देशों की भी अनेक आवश्यकताएं पूरी होंगी। जहां जर्मनी के साथ हरित एवं स्थायी विकास पर समझौता हुआ, वहीं ग्रीन हाइड्रोजन एवं अक्षय ऊर्जा पर सहयोग भी उल्लेखनीय है। इस यात्रा में 'माइग्रेशन एंड मॉबिलिटी' पर हुए समझौते से दोनों देश के संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे।

डेनमार्क की यात्रा से अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य भागीदारी और भी अधिक सुदृढ़ हुई है। ग्रीन प्रौद्योगिकी, ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय एवं स्थाई हरित विकास में सहयोग के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई तेज करने के संकल्प से दोनों देशों के बीच 'ग्रीन सामरिक भागीदारी' और भी अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं डेनमार्क की प्रधानमंत्री श्रीमती मेट्टे फ्रेडेरिकसेन के बीच विस्तृत वार्ता के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, डिजिटल एवं नवाचार के क्षेत्रों में विस्तार होगा। इनके अलावा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमशीलता के क्षेत्रों में समझौते हुए तथा पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक में सहयोग पर सहमति बनी। भारत-नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एवं आइसलैंड के नेताओं से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। देश वापस आने के रास्ते में फ्रांस में कुछ समय तक रुककर राष्ट्रपति मैक्रों से भी प्रधानमंत्री श्री मोदी की दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ करने के संबंध में चर्चा हुई। दोनों शीर्ष नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, असैनिक परमाणु सहयोग तथा जनता से जनता का संपर्क सहित अनेक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के पिछले दो वर्ष के दौरान भारत विश्व के एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। भारत ने न केवल इस महामारी की चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया, बल्कि अन्य देशों को भी उनके संकट के समय में दवाइयां, पीपीई किट ऑक्सीजन, टीके एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता की। जिस प्रकार से रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से विश्व के अनेक नेताओं ने अपील की, उससे अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत के बढ़ते हुए कद का आभास होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, युद्ध या प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता के अलावा, भारत ने कॉप-26 में जलवायु परिवर्तन पर पांच प्रतिबद्धताओं पर भी तेजी से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। भारत की पहल पर 'अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन' की स्थापना की पूरे विश्व में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ नेतृत्व में भारत आज वैश्विक दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है और पूरे विश्व के लिए आशा की एक नई किरण बनकर उभर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन देशों के साथ हुए समझौतों से यूरोप के साथ भारत की एक लंबी भागीदारी की शुरुआत हुई है तथा संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। ■

कोविड-19 वैश्विक महामारी के पिछले दो वर्ष के दौरान भारत विश्व के एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। भारत ने न केवल इस महामारी की चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया, बल्कि अन्य देशों को भी उनके संकट के समय में दवाइयां, पीपीई किट ऑक्सीजन, टीके एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता की

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

व्यापार, निवेश और नयी हरित साझेदारियों को मिला बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2-4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की सफल यात्रा की। इस तीन दिवसीय यात्रा के मध्य श्री मोदी ने व्यापार, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कई द्विपक्षीय बैठकें कीं तथा दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से व्यापार और निवेश संबंध आगे बढ़े, नयी हरित साझेदारियां बनीं, नवोन्मेष व कौशल विकास को लेकर सहयोग को बढ़ावा मिला तथा यूरोपीय साझेदारों से सहयोग की भावना को और मजबूती मिली

जर्मनी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दो मई को जर्मनी के संघीय चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज़ के निमंत्रण पर बर्लिन पहुंचे। श्री मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और चांसलर श्री स्कोल्ज ने संघीय चांसलर के कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगवानी की। इसके बाद दोनों राजनेताओं की बैठक आमने-सामने हुई, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।

इन चर्चाओं में समग्र रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम के मद्देनजर द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री द्वारा छठवें भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज़ के साथ दो मई को भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) के पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की। शुरुआती टिप्पणी में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जर्मनी साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बन सकती है। उन्होंने भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए जर्मनी के चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज़

दोनों देशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने आईजीसी के विभिन्न पहलुओं संबंधी अपनी बैठकों पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की:

- विदेश मामले और सुरक्षा
- आर्थिक, वित्तीय नीति और वैज्ञानिक एवं सामाजिक विनिमय
- जलवायु, पर्यावरण, सतत विकास और ऊर्जा

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और सचिव डीपीआईआईटी श्री अनुराग जैन ने भारत की ओर से प्रजेंटेशन दिया।

हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर

पूर्ण सत्र का समापन प्रधानमंत्री श्री मोदी और चांसलर श्री स्कोल्ज़ द्वारा हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र (जेडीआई) पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। यह साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु कार्रवाई पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है। इसके तहत जर्मनी 2030 तक 10 अरब यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता के लिए सहमत हो गया है। साझेदारी को उच्च स्तरीय समन्वय और राजनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए यह जेडीआई आईजीसी के दायरे में एक मंत्रिस्तरीय तंत्र भी बनाएगा।

बर्लिन में व्यापार गोलमेज बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज के साथ दो मई को एक व्यापार गोलमेज बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुधारों पर जोर दिया और भारत में स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने व्यापार जगत की शीर्ष

कोपेनहेगन, डेनमार्क में संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन

हस्तियों को भारत के युवाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

इस कार्यक्रम में दोनों सरकारों के उच्च स्तर के प्रतिनिधियों और दोनों पक्षों के चयनित सीईओ की भागीदारी हुई, जिन्होंने जलवायु सहयोग, आपूर्ति शृंखला तथा अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा में हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री की जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के बर्लिन स्थित थियेटर एम पॉट्सडैमर प्लाट्ज़ में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। जर्मनी में जीवंत भारतीय समुदाय के 1600 से अधिक सदस्यों, जिनमें छात्र, शोधकर्ता और पेशेवर शामिल थे, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मोदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था और समाज में उनके योगदान को रेखांकित किया और वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उन्हें भारत की पहल 'वोकल फॉर लोकल' में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

डेनमार्क

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन के निमंत्रण पर 3-4 मई के दौरान डेनमार्क की यात्रा की। श्री मोदी ने तीन मई को प्रधानमंत्री सुश्री फ्रेडरिकसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने आमने-सामने के प्रारूप में बातचीत की, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-डेनमार्क हरित सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इस बातचीत में अक्षय ऊर्जा, खास तौर पर अपतटीय पवन ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही साथ कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिपिंग, जल तथा आर्कटिक में सहयोग जैसे विषय शामिल रहे।

श्री मोदी ने भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में डेनमार्क की कंपनियों के सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री सुश्री फ्रेडरिकसन ने डेनमार्क में भारतीय कंपनियों की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच लोगों के बढ़ते आपसी संबंधों की सराहना की और प्रवासन व गतिशीलता साझेदारी पर आशय घोषणा का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने कोपेनहेगन में भारत-डेनमार्क व्यापार मंच में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसन और डेनमार्क के राजकुमार एच.आर.एच. फ्रेडरिक के साथ संयुक्त रूप से तीन मई को डेनमार्क उद्योग परिसंघ में आयोजित भारत-डेनमार्क व्यापार मंच में भाग लिया।

> **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने भारत-डेनमार्क हरित सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इस बातचीत में अक्षय ऊर्जा, खास तौर पर अपतटीय पवन ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही साथ कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिपिंग, जल तथा आर्कटिक में सहयोग जैसे विषय शामिल रहे**

श्री मोदी ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के पूरक कौशल पर जोर दिया और डेनमार्क की कंपनियों को हरित प्रौद्योगिकियों, कोल्ड चेन, कचरे से सम्पत्ति निर्माण, शिपिंग और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में भारत में मौजूद अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत के व्यापार अनुकूल दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदायों को सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री सुश्री फ्रेडरिकसन ने दोनों देशों के बीच एक सेतु बनाने में व्यापारिक समुदायों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इस आयोजन में दोनों देशों के व्यवसायियों की भागीदारी निम्न क्षेत्रों में देखी गई:

- हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण
- ऊर्जा स्वतंत्रता और नवीकरणीय ऊर्जा
- जल, पर्यावरण और कृषि
- अवसंरचना, परिवहन और सेवाएं

कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ तीन मई को कोपेनहेगन स्थित बेला सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के 1000 से अधिक सदस्यों, जिनमें छात्र, शोधकर्ता, पेशेवर और व्यवसायी शामिल थे, ने इस कार्यक्रम

में भाग लिया।

श्री मोदी ने सुश्री फ्रेडरिक्सन की गर्मजोशी एवं भारतीयों के प्रति सम्मान की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हरित विकास के लिए मौलिक समाधान खोजने में मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने डेनमार्क में भारतीय समुदाय द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की। उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डाला तथा भारत एवं डेनमार्क के बीच और अधिक सहयोग को आमंत्रित किया।

डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत

डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने चार मई को कोपेनहेगन के ऐतिहासिक अमालियनबोर पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क के राजसिंहासन पर महारानी के आरोहढ़ की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्हें बधाई दी।

श्री मोदी ने हाल के वर्षों में भारत-डेनमार्क के सम्बंधों की बढ़ती प्रगाढ़ता,विशेषकर हरित रणनीतिक साझेदारी के विषय के बारे में महारानी को अवगत कराया। उन्होंने सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने में डेनमार्क के शाही परिवार की भूमिका की भी प्रशंसा की।

दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में चार मई को डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन, आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोर, स्वीडन की प्रधानमंत्री सुश्री मैग्डेलीना एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन के साथ भाग लिया।

इस शिखर सम्मेलन ने 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से भारत-नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। महामारी के बाद आर्थिक सुधार (रिकवरी), जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नवाचार, डिजिटलीकरण और हरित एवं स्वच्छ विकास आदि क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई।

स्थायी महासागर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। श्री मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को विशेष रूप से भारत की सागरमाला परियोजना समेत जल से जुड़ी (ब्लू इकॉनमी) अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्कटिक नीति, आर्कटिक क्षेत्र में भारत-नॉर्डिक सहयोग के विस्तार के लिए एक अच्छी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने नॉर्डिक देशों के सोवेरेन वेल्थ फण्ड को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। क्षेत्रीय और वैश्विक

कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिख

घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक-शिखर सम्मेलन के दौरान कोपेनहेगन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनस गहर स्टोर के साथ बैठक की। अक्टूबर, 2021 में प्रधानमंत्री श्री स्टोर द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से दोनों राजनेताओं के बीच यह पहली बैठक थी।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के तहत जारी गतिविधियों की समीक्षा की और सहयोग के भावी क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि नॉर्वे का कौशल और भारत की संभावनाएं प्राकृतिक तौर पर एक-दूसरे की पूरक हैं।

दोनों नेताओं ने जल से जुड़ी अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं, हरित पोत परिवहन, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की क्षमता पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद् के सदस्य देशों के रूप में भारत और नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र में पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर एक-दूसरे को सहयोग देते रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान कोपेनहेगन में स्वीडन की प्रधानमंत्री सुश्री मैग्डेलीना एंडरसन के साथ बैठक की। दोनों राजनेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। भारत और स्वीडन के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध

र सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

रहे हैं जो समान मूल्यों, मजबूत व्यापार, निवेश तथा अनुसंधान व विकास में आपसी सहयोग एवं वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश और अनुसंधान एवं विकास सहयोग; इस आधुनिक संबंध के आधार-स्तम्भ हैं।

पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की 2018 की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना को अंगीकार किया था और एक संयुक्त नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे।

इस बैठक में दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लीड आईटी पहल की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। यह 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन में उद्योग परिवर्तन पर नेतृत्व समूह (लीडआईटी) का गठन करने के लिए भारत-स्वीडन की संयुक्त वैश्विक पहल थी, ताकि दुनिया के सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जक उद्योगों का कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर जाने में मार्गदर्शन किया जा सके। इसकी सदस्यता 16 देशों और 19 कंपनियों के साथ मिलकर अब 35 हो गई है।

दोनों राजनेताओं ने नवाचार, जलवायु प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्य, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष, रक्षा, नागरिक उड्डयन, आर्कटिक, ध्रुवीय अनुसंधान, स्थायी खनन और व्यापार तथा आर्थिक संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी। दोनों पक्षों ने 16 मार्च, 2021 को आयोजित द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणाम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष जाहिर किया।

दोनों नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि निरंतरता, डिजिटलीकरण और विज्ञान व शिक्षा में सहयोग जैसे क्षेत्र द्विपक्षीय संबंध के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की मोबाइल प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ तकनीक और स्मार्ट ग्रिड जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की।

श्री मोदी ने फिनलैंड की कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने और भारतीय बाजार में खासतौर से दूरसंचार बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तनों में मौजूद विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अधिक सहयोग पर भी चर्चा हुई।

फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक

कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से लौटते समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 मई को फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की। पेरिस में प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ आमने-सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। दोनों

पेरिस के एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की

नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, नीली अर्थव्यवस्था, असैन्य परमाणु और लोगों के लोगों से संबंधों में सहयोग सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के पहलू पर भी बात की और वैश्विक भलाई के लिए भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को एक ताकत बनाने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। श्री मोदी के फ्रांस दौरे ने न केवल दोनों देशों बल्कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत मित्रता और सद्भाव को प्रदर्शित किया। उन्होंने राष्ट्रपति श्री मैक्रों को जल्द भारत आने का न्योता भी दिया। ■

तेलंगाना में कमल का खिलना तय है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 5 मई, 2022 को तेलंगाना के महबूबनगर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश की भ्रष्ट एवं अराजक टीआरएस सरकार पर जमकर प्रहार किया। इससे पहले हैदराबाद के शमसाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर श्री नड्डा का वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात् श्री नड्डा ने महबूबनगर में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और विभिन्न विषयों पर पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बंदी संजय कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन डी.के. अरुणा, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के. लक्ष्मण, मध्य प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर राव, श्री एटला राजेंद्र, श्री राजा सिंह और श्री अरविंद धर्मपुरी सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी, पार्टी विधायक और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

टीआरएस का नाम 'तेलंगाना राष्ट्र समिति नहीं' बल्कि 'तेलंगाना रजाकार समिति' होना चाहिए। केसीआर सरकार बस 'बांटो और राज करो' की नीति के तहत काम कर रही है

श्री नड्डा ने कहा कि दुब्बका में भाजपा की जीत का धमाका क्या हुआ और हुजूराबाद में हुजूर क्या गिरे कि केसीआर तिलमिला गए हैं। हुजूराबाद में हुजूर का गिरना और दुब्बका में भाजपा की जीत का परचम, तेलंगाना में भाजपा की अगले धमाके वाली जीत की निशानी है। तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पड़ी है। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि वे तेलंगाना में परिवर्तन के लिए तैयार हैं, वे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार देखना चाहते हैं। जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में कमल का खिलना तय है।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार जी की तेलंगाना में परिवर्तन की 'प्रजा संग्राम यात्रा' को प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इस यात्रा में आज की जनसभा के दौरान जो जनसैलाब उमड़ा है, वही बताता है कि जनता का भाजपा के प्रति कितना स्नेह है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार एक जवाबदेह, रिस्पोंसिव, प्रो-एक्टिव और प्रो-पुअर सरकार है। कोरोना मैनेजमेंट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के तमाम देश कोरोना के सामने अपने आप को निरीह और असहाय पा रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल 135 करोड़ देशवासियों को स्वदेशी कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया बल्कि गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीबों के दो वक्त की रोटी की भी चिंता की। साथ ही, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', 'वोकल फॉर लोकल' और 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के माध्यम से उन्होंने देश के अर्थचक्र की गति को भी धीमा नहीं पड़ने दिया। जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लॉकडाउन के समय देशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील कर रहे थे, तब केसीआर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे। तेलंगाना की जनता जानती है कि केसीआर ने किस तरह विधानसभा में कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाया था। जब प्रजातंत्र की आवाज उठने लगी तो कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर केसीआर सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को

अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया। ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है।

श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना त्रासदी के समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत मदद पहुंचाया। प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में आज भारत बदल रहा है। पहले भारत केवल आयात करने वाले देश के रूप में जाना जाता था लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक निर्यातक राष्ट्र के रूप में उभरा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 400 बिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात कर एक रिकॉर्ड कायम किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। कॉटन की एमएसपी को 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तेलंगाना में भेड़ और बकरी के डेवलपमेंट के लिए अलग से 4,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। देश के लगभग 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत से जुड़ चुके हैं। इनमें से लगभग 3.11 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। देश में अब तक आयुष्मान भारत पर लगभग 23,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन केसीआर सरकार ने अब तक तेलंगाना के लगभग 26 लाख गरीब लोगों को इससे वंचित रखा है।

टीआरएस सरकार पर हमला जारी रखते हुए श्री नड्डा ने कहा कि केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। सिंचाई की सभी योजनाओं में केसीआर सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कालेश्वरम सिंचाई योजना तो केसीआर सरकार के लिए भ्रष्टाचार का एटीएम बन चुकी है। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट केवल 20,000 करोड़ रुपये का था लेकिन आज यह 1.20 लाख करोड़ रुपये की हो गई है लेकिन अब तक इस सिंचाई परियोजना से खेतों को पानी नसीब नहीं हुई है। इसी तरह रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन, मिशन भागीरथ, मिशन काकतीय सहित तमाम परियोजनाएं फेल हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि जब राज्य में गलत सरकार होती है तो इसी तरह भ्रष्टाचार का शासन होता है लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आती है तो चहुँ ओर विकास होता है। तेलंगाना की केसीआर सरकार लैंड माफिया का काम कर रही है और तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। मेरे हिसाब से टीआरएस का नाम 'तेलंगाना राष्ट्र समिति नहीं' बल्कि 'तेलंगाना रजाकार समिति' होना चाहिए। केसीआर सरकार बस 'बांटो और राज करो' की नीति के तहत काम कर रही है लेकिन तेलंगाना की जनता लड़ना जानती है और जनता अपना हक़ और हिस्सा लेकर रहेगी।

उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की हर जनोपयोगी योजना का नाम बदलकर अपने नाम से उसे तेलंगाना में लागू कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को बदलकर टू-बेडरूम हाउसिंग योजना कर दी गई है। इसी तरह समग्र शिक्षा योजना का नाम बदल दिया गया और मातृ वंदन योजना का नाम बदलकर केसीआर किट कर दिया गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। केसीआर सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं को तेलंगाना में सही से लागू नहीं होने देती। मैं प्रजा संग्राम यात्रा को शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप गांव-गांव, घर-घर जाएं और श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए केसीआर सरकार की पोल खोलें। केसीआर को प्रजातंत्र में कोई यकीन नहीं है, वे तरह-तरह के हथकंडे अपनाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रजातांत्रिक तरीके से केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ■

दिल्ली में भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन

'भाजपा के लिए कार्यालय, कार्यकर्ताओं के संस्कार के केंद्र होते हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 मई, 2022 को दक्षिणी दिल्ली में भाजपा के एक नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से इस कार्यालय का उपयोग करते हुए बूथ में भाजपा संगठन को ताकतवर बनाने की अपील की। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए पांच "क" की जरूरत होती है - कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकारिणी, कोष और कार्यालय। आज ओखला में दक्षिणी दिल्ली के भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए इसे जन-जन की पार्टी बनाया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 521 जिला भाजपा कार्यालय का काम चल रहा है और 200 से अधिक जिला भाजपा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। यहां दिल्ली में भी 14 कार्यालय बनने हैं और आज 10वां कार्यालय बन कर तैयार हो चुका है। भाजपा के लिए कार्यालय, कार्यकर्ताओं के संस्कार के केंद्र होते हैं। हमें इस अवसर पर उन कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान को भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर निस्वार्थ भाव से 1952 से लेकर आज तक अहर्निश कार्य किया है। यह कार्यालय एक दिन की उपज नहीं है बल्कि इसके लिए हमारी चार-चार पीढ़ियों ने अपने-आप को खपाया है। ■

'हमें अपनी विचारधारा को यशस्वी बनाकर देश को निरंतर आगे बढ़ाना है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 अप्रैल, 2022 को गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल, मेमनगर, कर्णावती में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और गुजरात के विकास की विस्तार से चर्चा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के सभी पदाधिकारी, सभी मोर्चा के गुजरात में रहने वाले राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य, सभी प्रकोष्ठों के सदस्य, प्रदेश भाजपा के सभी विभागों के सदस्य, सभी प्रदेश प्रवक्ता, सह-प्रवक्ता, जिला एवं महानगरों के भाजपा प्रभारी, जिला एवं महानगरों के पार्टी पदाधिकारी, जिला/महानगर के सभी मोर्चों के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष एवं महासचिव उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का मंत्र है - सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश में आज भाजपा को छोड़कर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखी के कारण देश में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ और कालांतर में ये पार्टियां परिवार की पार्टी बन कर रह गईं।

> उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि देश की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को सिरे से ख़ारिज कर दिया है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकासवाद, राष्ट्रवाद और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की राजनीति पर मुहर लगाई है

उन्होंने कहा कि पहले कोई भी वैक्सीन देश में वर्षों बाद आ पाते थे लेकिन इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 9 महीने में ही देश में दो-दो विश्वस्तरीय वैक्सीन विकसित हुआ और इसका रोल-आउट भी सुनिश्चित हुआ। अब तक लगभग 186 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किये जा चुके हैं। गुजरात में भी लगभग 97 प्रतिशत से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं इसके लिए गुजरात की भाजपा सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। देश में वैक्सीनेशन के साथ-साथ ही हमने दुनिया के लगभग 100 देशों को कोरोना काल में वैक्सीन मैत्री के तहत सहायता भी पहुंचाई।

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत के 'ऑपरेशन गंगा' की चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने युद्धग्रस्त यूक्रेन से 23,000 देशवासियों (जिसमें अधिकतर छात्र थे) की सकुशल स्वदेश वापसी कराई जबकि दुनिया के किसी भी देश ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की इस तरह की पहल नहीं की। गुजरात के भी लगभग ढाई हजार छात्रों को यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया। पूरे बचाव अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता लगातार छात्रों के परिजनों के संपर्क में रहे और उनकी हौसला-अफजाई की। मतलब यह कि मोदी है तो मुमकिन है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि देश की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को सिरे से ख़ारिज कर दिया है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकासवाद, राष्ट्रवाद और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की राजनीति पर मुहर लगाई है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बहुत फर्क पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यह माना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते श्री नरेन्द्र मोदी सरकार लोगों को अत्यधिक गरीबी की जद में जाने

से रोकने में सफल रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पिछले आठ वर्षों में भारत में अत्यंत गरीबी की संख्या में 12.3 प्रतिशत की भारी कमी आई है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व के बल पर ही संभव हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि कोरोना लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को सुरक्षित भी किया, भारतवासियों के दो वक्त की रोटी की भी चिंता की और देश के अर्थतंत्र की गति को भी धीमी नहीं पड़ने दिया। आज भारत एक्सपोर्ट हब के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित हो रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल 6-6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत दिए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी चार-चार पीढ़ियां खप गईं इस सपने को साकार करने हेतु संघर्ष करने में कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति है जिसके बल पर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 भी धराशायी हुआ। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से और सर्वसम्मति से सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बन रहा है। वर्षों बाद मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली है जबकि यह सर्वविदित है कि कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटकर मुस्लिम महिलाओं को अभिशापित जिंदगी जीने पर विवश कर दिया था।

श्री नड्डा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लें कि हमें अपनी विचारधारा को यशस्वी बनाकर देश को निरंतर आगे बढ़ाना है। हमें गांव-गांव, घर-घर जाकर, लोगों से मिलना है और समृद्ध गुजरात एवं खुशहाल भारत के लिए काम करना है।

प्रेस वार्ता

'जन-जन का सहयोग और समर्थन हमें निरंतर मिल रहा है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 अप्रैल 2022 को गांधीनगर (गुजरात) स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय 'श्री कमलम्' में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और गुजरात के विकास की विस्तार से चर्चा करते हुए राज्य की जनता से एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में डबल इंजन की गरीब-कल्याणकारी सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी. आर. पाटिल सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने 'श्री कमलम्' में एक विशेष बैठक भी की जिसमें प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य, प्रदेश से भाजपा सांसद, भाजपा विधायक, महानगरपरिषद् के महापौर, उप-महापौर, स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन, जिला परिषद् अध्यक्ष और पार्टी के पूर्व सांसद एवं विधायक भी उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। चाहे जनता से जुड़े हुए विषय हों अथवा हमारी पार्टी व संगठन से जुड़े विषय, गुजरात हमेशा देश के पुनर्निर्माण की प्रयोगशाला रही है। गुजरात की धरती से आगे बढ़कर भाजपा ने दुनिया को यह रास्ता दिखाया कि जन-जन के प्रति समर्पित रहते हुए कैसे संगठन का विकास हो सकता है और उस संगठन के माध्यम से कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। पहले गुजरात के महामंत्री के रूप में, फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने संगठन को जन-जन से जोड़ा और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास के एक नए मॉडल को प्रतिस्थापित किया जिसका अनुसरण आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश भी कर रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किये, गुजरात को जिस तरह विकास का मॉडल बनाया था, उसका प्रतिबिंब आज हम पूरे देश में देख रहे हैं।

गुजरात की विकास यात्रा पर चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि गुजरात का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 17.4 प्रतिशत है जो विगत 8 वर्षों में सबसे अधिक है। 2021-22 में गुजरात का जीएसडीपी 19,44,107 करोड़ रुपये था जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 16,55,917 करोड़ रुपये था। नीति आयोग के अनुसार, गुजरात फाइनेंसियल मैनेजमेंट में देश में पहले स्थान पर है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वृद्धि के बावजूद विगत 20 वर्षों में गुजरात का कोई ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देशन में जहां एक ओर गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार प्रदेश को विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर, प्रदेश अध्यक्ष श्री सी. आर. पाटिल के नेतृत्व में पार्टी और संगठन भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की डबल इंजन वाली भूपेन्द्र पटेल सरकार रिस्पोंसिव है, जवाबदेह है और गरीबों के सशक्तीकरण के लिए कटिबद्ध है। साथ ही, पार्टी कार्यकर्ता भी सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं को वैचारिक और राजनीतिक रूप से जमीन पर उतारने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात में हुए सभी उपचुनावों, नगरपालिका, नगर निगम और तालुका चुनावों में भाजपा ने 90 प्रतिशत से अधिक सीटें जीती हैं, यह दर्शाता है कि जन-जन का सहयोग और समर्थन निरंतर हमें मिल रहा है। ■

जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध लड़ने को प्रतिबद्ध भाजपा: अमित शाह

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 05 मई, 2022 को कोलकाता पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान श्री शाह ने सिलीगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, मैत्री संग्रहालय का शिलान्यास किया और हरिदासपुर में प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। श्री शाह ने यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की सूची में दुर्गा पूजा के शिलालेख को शामिल करने पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम-मुक्ति-मातृका में भी भाग लिया और पश्चिम बंगाल भाजपा के सांसदों, विधायकों एवं पदाधिकारियों से मुलाकात की।

सिलीगुड़ी में रैली

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया जाएगा। "ममता दीदी केवल बंगाल में घुसपैठ होते देखना चाहती हैं जबकि हमारे शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिल पाती है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि तृणमूल को इस बात को स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए कि सीएए एक वास्तविकता था, एक वास्तविकता है और एक वास्तविकता बना रहेगा।"

श्री शाह ने बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद कानून लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि वह तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी शासन को खत्म नहीं कर देती और बंगाल में लोकतंत्र बहाल नहीं कर देती। श्री शाह ने यह भी कहा कि भाजपा 'कट-मनी' के माध्यम से जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की संस्कृति के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "मैं विधानसभा में भाजपा की संख्या तीन से बढ़ाकर 77 करने के लिए बंगाल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें उम्मीद थी कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता दीदी खुद को सुधार लेंगी। इसके लिए हमने पूरे एक साल तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं बदली और राज्य में अभी भी जंगलराज कायम है।"

"दीदी ने हमेशा गोरखा भाइयों और बहनों को गुमराह किया है। मैं आज उन्हें यह बताने आया हूं कि अगर कोई एक पार्टी है जो गोरखाओं के हित में सोचती है, तो वह भाजपा है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनकी सभी समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान संविधान के दायरे में ही मिल जाएगा।"

ठाकुर पंचानन बर्मा और तेनजिंग नोर्गे शेरपा को श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में समाज सुधारक ठाकुर पंचानन बर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, "ठाकुर पंचानन बर्मा एक महान नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के पिछड़े लोगों के सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वह हमारे राजबांशी समुदाय के अग्रणी व्यक्तित्वों में से एक थे, आज मैं इस महान को श्रद्धांजलि देता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान दार्जिलिंग के तेनजिंग नोर्गे शेरपा को भी सम्मान और श्रद्धांजलि दी, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। श्री शाह ने अपने संदेश में कहा, "29 मई, 1953 के दिन एक नया इतिहास रचा गया था जब दार्जिलिंग के तेनजिंग नोर्गे शेरपा न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। वह हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"

भारत विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर काबिज होगा

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 06 मई, 2022 को कहा कि अब से 25 साल बाद भारत विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर काबिज होगा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और यूनेस्को द्वारा बंगाल की दुर्गा पूजा को एक अमूर्त वैश्विक विरासत के रूप में घोषित करने के उपलक्ष्य में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस वैश्विक संस्था का सम्मान पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हर क्षेत्र में - शिक्षा, कला, रक्षा, आप केवल नाम लीजिए, भारत ने बहुत प्रगति की है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महान शक्ति के तौर पर उभरा है और सम्मान प्राप्त कर रहा है। जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में पहुंचेगा, तो भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर आ जाएगा।

'स्व. चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 6 मई, 2022 काशीपुर (पश्चिम बंगाल) में भाजपा कार्यकर्ता श्री अर्जुन चौरसिया की नृशंस हत्या पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। विदित हो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के बीच सुबह भाजपा नेता अर्जुन चौरसिया का शव कोलकाता के चितपुर में लटका मिला था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही श्री शाह ने 6 मई के अपने सभी स्वागत कार्यक्रम और कई अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिए। वे दिवंगत अर्जुन चौरसिया जी के घर गए और वहां उन्होंने उनके परिजनों से मुलाक़ात की। उन्होंने श्री चौरसिया के परिजनों को आश्वस्त किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और वे श्री चौरसिया को न्याय दिलाकर रहेंगे।

स्व. अर्जुन चौरसिया के घर के बार मीडिया को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री अर्जुन चौरसिया की राजनीतिक रूप से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की ये फ़रियाद है कि श्री अर्जुन चौरसिया की जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हुआ है। इसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक हत्या की परंपरा फिर से शुरू कर दी गई है। पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर निशाना बनाने के अनेक उदाहरण हमारे सामने आये हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री अर्जुन चौरसिया की हत्या की घोर निंदा करती है और हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता न्याय की अदालत के सामने जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि श्री चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

उन्होंने कहा कि मैं आज पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को यह

बताना चाहता हूं कि राजनीतिक हिंसा एवं राजनीतिक हत्या की राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोधियों की आवाज को कुचलना और इसे हिंसा एवं हत्या जैसे जघन्य वारदातों से डराने का प्रयास करना तृणमूल कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। मैंने श्री चौरसिया के परिवार से मुलाक़ात की है। श्री चौरसिया की बूढ़ी दादी को भी बख्शा नहीं गया, उन्हें भी मारा गया और उनके अनुसार जोर-जबरदस्ती से श्री चौरसिया के पार्थिव शरीर को भी परिवार से छीना गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इस वारदात की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह श्री चौरसिया के परिवार के साथ एकजुट होकर खड़ी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी इस नृशंस घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है और आज ही गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। ■

बंगाल की दुर्गा पूजा के लिए यूनेस्को के सम्मान के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "यह न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है।"

श्री शाह ने कहा, "दुर्गा पूजा के दौरान देवी की उपासना की जाती है। 'स्त्री शक्ति' को समर्पित यह भाव महिला सशक्तिकरण के लिए है। वह एक शक्ति है जिसे सभी देवताओं- हिंदू त्रिमूर्ति- ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने राक्षस को मारने के लिए बुलाया था। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि सदियों से नारी शक्ति का जश्न कैसे मनाया जाता है।"

गृह मंत्री ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने बलिदान देकर देश को स्वतंत्र करवाया था और जिसके कारण आज एक स्वतंत्र माहौल में हम सांस ले रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में बंगाल के खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों का भी उल्लेख किया। ■

मिजोरम एमएडीसी चुनाव: भाजपा ने 12 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

दक्षिण मिजोरम के सियाहा जिले में 25 सदस्यीय मारा स्वायत्त जिला परिषद (एमएडीसी) के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इन चुनावों में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एमएडीसी चुनाव परिणाम 09 मई, 2022 को घोषित किए गए थे।

भाजपा ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को नौ और कांग्रेस को चार सीटें मिलीं। ■

'वाम मोर्चा सरकार केरल में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 06 मई, 2022 को केरल के कोझीकोड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों का उत्साह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का केरल में भविष्य बहुत उज्ज्वल है और वह एक मजबूत ताकत के रूप में उभरेगी।

उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार हमेशा कहती रही है कि वह समाज के हर वर्ग के साथ समान व्यवहार करती है। लेकिन तथ्य यह है कि वाम मोर्चा सरकार केरल में इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इस्लामिक आतंकवाद को सीपीएम सरकार से संरक्षण और समर्थन मिल रहा है और केरल इस्लामिक आतंकवाद का प्रमुख केंद्र बन गया है।

केरल में तेजी से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर समाज असहज और परेशान है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता इस तरह के मुद्दों को बार-बार उठाते रहे हैं।

केरल में हुई 125 राजनीतिक हत्याएं

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एलडीएफ शासन में केरल की कानून व्यवस्था की सच्चाई इस बात से ही उजागर हो जाती है कि प्रदेश में संगठित अपराध बढ़ा है और पिछले तीन वर्षों में हत्याओं के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दुर्भाग्य से, एलडीएफ केरल में इस प्रकार के शासन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिनाराई विजयन सरकार शासन के हर पहलू में पूरी तरह विफल रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी काफी वृद्धि हुई है।

श्री नड्डा ने कहा, "मैं यह जानकर स्तब्ध हूं कि पिछले 15 वर्षों में 125 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इनमें से ज्यादातर हत्याएं कन्नूर जिले में हुईं, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। पिछले 3 वर्षों में कुल 1019 से अधिक हत्याएं हुई हैं।

हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे

पलक्कड़ में रा.स्व.संघ कार्यकर्ताओं श्रीनिवासन और श्री ए. संजीत पर क्रूर हमले की ताजा घटना प्रदेश सरकार द्वारा आपराधिक और सांप्रदायिक तत्वों को दिए गए समर्थन का एक ज्वलंत उदाहरण है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "मैं केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं जो प्रदेश प्रायोजित हिंसा से लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और दोषियों को सजा दिलायेंगे।"

प्रमुख बिंदु

- भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहां 68,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं।
- एक साल के भीतर 100 यूनिकॉर्न बने हैं।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रोत्साहन से ही 2021-22 में भारत ने खादी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसने हमारे कारीगरों, श्रमिकों और किसानों को सशक्त बनाया है।
- हमने 'वन नेशन—वन राशन कार्ड' योजना शुरू की है जो जनता और श्रमिक वर्ग के लिए किए गए सबसे बड़े सुधारों में से एक है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द किया गया है और अब जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है।
- पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहयोग मिला है, जिसमें से 37.31 लाख किसान केरल के हैं।
- देश में 12 करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी का कनेक्शन मिल है, जल जीवन मिशन के 70.68 लाख लाभार्थी केरल से हैं।
- वित्तीय समावेशन योजना के तहत जन-धन योजना में 45 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें से 45.85 लाख लोग केरल के हैं।
- बीपीसीएल की 6,000 करोड़ रुपये की पेट्रोकेमिकल परियोजना केरल को आवंटित की गई है।
- समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान 'विज्ञान सागर', कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और कई अन्य परियोजनाएं केरल में आ रही हैं।
- भारतमाला परियोजना के तहत अब तक 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 49 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और केरल को 4,035 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सागरमाला परियोजना के तहत 65 परियोजनाएं चल रही हैं और इस पर 18,081 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। ■

अप्रैल, 2022 में अब तक का सर्वाधिक 'सकल जीएसटी राजस्व संग्रह' 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा

अप्रैल, 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे अधिक संग्रह है, जो पिछले सर्वाधिक संग्रह से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है, पिछले महीने में 1,42,095 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक मई को जारी विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल, 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 33,159 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 41,793 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 81,939 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 36,705 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,649 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 857 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

अप्रैल, 2022 में जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे अधिक संग्रह है, जो पिछले सर्वाधिक संग्रह से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है, पिछले महीने में 1,42,095 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

केंद्र सरकार ने आईजीएसटी से 33,423 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 26,962 करोड़ रुपये का एसजीएसटी में निपटान किया है। अप्रैल, 2022 के महीने में नियमित निपटान के बाद केन्द्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 66,582 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 68,755 करोड़ रुपये रहा।

अप्रैल, 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में संग्रह किए गए जीएसटी राजस्व से 20 प्रतिशत अधिक है। इस मास के दौरान वस्तुओं के आयात से

प्राप्त राजस्व 30 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेन-देन से प्राप्त राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

पहली बार सकल जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। मार्च, 2022 के महीने में कुल 7.7 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए, जो फरवरी, 2022 के महीने में उत्पन्न 6.8 करोड़ ई-वे बिल से 13% अधिक है। यह तेज गति से व्यावसायिक गतिविधि में सुधार को दर्शाता है।

अप्रैल, 2022 के महीने में 20 अप्रैल को एक दिन में अब तक का सबसे अधिक कर संग्रह हुआ और उस दिन शाम 4 बजे से शाम 5 बजे के दौरान एक घंटे के दौरान सबसे अधिक कर संग्रह देखा गया। 20 अप्रैल, 2022 को 9.58 लाख लेनदेन के माध्यम से 57,847 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और 4-5 बजे के दौरान 88,000 लेनदेन के माध्यम से लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। पिछले साल (उसी तारीख को) सबसे अधिक एक दिन का भुगतान हुआ था, जब 7.22 लाख लेनदेन के माध्यम से 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ और सर्वाधिक एक घंटे का संग्रह (पिछले साल इसी तारीख को 2 बजे दोपहर) 65,000 लेनदेन के माध्यम से 6,400 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था।

अप्रैल, 2022 के दौरान जीएसटीआर-3बी में 1.06 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 97 लाख मार्च, 2022 के महीने से संबंधित थे, जबकि अप्रैल, 2021 के दौरान कुल 92 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे। इसी तरह, अप्रैल, 2022 के दौरान जीएसटीआर-1 में जारी किए गए चालानों के 1.05 करोड़ विवरण दाखिल किए गए। महीने के अंत तक अप्रैल, 2022 में जीएसटीआर-3बी का फाइलिंग प्रतिशत 84.7% रहा, जबकि अप्रैल, 2021 में 78.3% था और अप्रैल, 2022 में जीएसटीआर-1 के लिए फाइलिंग प्रतिशत 83.1% था, जबकि अप्रैल, 2021 में 73.9% था।

यह अनुपालन व्यवहार में स्पष्ट सुधार दर्शाता है, जो कर प्रशासन द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं को प्रेरित करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों का परिणाम है। ■

जेम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की खरीद 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची

रक्षा मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी ई-मार्केट (जेम) पोर्टल के माध्यम से खरीद के आदेश 15,047.98 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 250 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई। अगस्त, 2016 में जेम की शुरुआत पुरानी निविदा प्रक्रिया में सुधार करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी व पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी।

जेम को शुरू किए जाने के बाद बहुत ही कम समय में रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल अभियान को अपनाया है और पूरी दृढ़ता के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जमीनी स्तर पर कई चुनौतियों के बावजूद इसके परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। ■

भारत के सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 254.4 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया

भारत का समग्र निर्यात (अर्थात सेवा एवं वस्तु क्षेत्र) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 676.2 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गया। वहीं, वित्त वर्ष 2019-20 तथा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश का समग्र निर्यात क्रमशः 526.6 अरब डॉलर तथा 497.9 अरब डॉलर रहा था

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा चार मई को जारी एक बयान के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात ने वित्त वर्ष 2021-22 में 254.4 अरब डॉलर का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वित्त वर्ष 2021-22 में अर्जित नए रिकॉर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित 213.2 अरब डॉलर के पिछले कीर्तिमान को ध्वस्त किया है। इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र निर्यात ने मार्च, 2022 के दौरान 26.9 अरब डॉलर की सर्वकालिक मासिक ऊंचाई को छुआ है।

अप्रैल-दिसंबर, 2021 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सेवा क्षेत्र निर्यात में अन्य व्यवसाय सेवाओं तथा परिवहन के अतिरिक्त दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना

सेवाएं योगदान देने में शीर्ष स्थान पर रहीं हैं।

भारत का समग्र निर्यात (अर्थात सेवा एवं वस्तु क्षेत्र) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 676.2 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गया, क्योंकि सेवा एवं वस्तु क्षेत्र दोनों ने ही वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च निर्यात रिकॉर्ड दर्ज किया। भारत का समग्र निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 तथा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्रमशः 526.6 अरब डॉलर तथा 497.9 अरब डॉलर रहा था।

भारत के वस्तु व्यापार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 400 अरब डॉलर से अधिक की ऐतिहासिक ऊंचाई दर्ज कराई थी तथा यह 421.8 अरब डॉलर रहा था, जोकि वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में क्रमशः 44.6 प्रतिशत तथा 34.6 प्रतिशत की शानदार वृद्धि इंगित करती है। ■

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) को दिसंबर, 2024 तक जारी रखने को मिली मंजूरी

पीएम-स्वनिधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। 25 अप्रैल, 2022 तक 31.9 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 29.6 लाख ऋणों के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किये गये

गत 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाकर दिसबंर, 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। इसके परिप्रेक्ष्य में रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने, डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया है।

इस योजना के जरिये रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में ऋण देने के लिये 5,000 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। मंत्रिमंडल की इस मंजूरी से ऋण की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है जिसके परिणामस्वरूप रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।

रेहड़ी-पटरी वालों के लिये कैश-बैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए बजट को भी बढ़ाया गया है। आशा की जाती है कि इस मंजूरी से शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

पीएम-स्वनिधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। 25 अप्रैल, 2022 तक 31.9 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 29.6 लाख ऋणों के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किये गये। जहां तक द्वितीय ऋण का प्रश्न है, तो उसके मद्देनजर 2.3 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई और 1.9 लाख ऋणों के हिसाब से 385 करोड़ रुपये जारी किये गये। लाभार्थी रेहड़ी-पटरी वालों ने 13.5 करोड़ से अधिक का डिजिटल लेन-देन किया और उन्हें 10 करोड़ रुपये का कैश-बैक भी मिला। सब्सिडी ब्याज के रूप में 51 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया।

यह योजना जून, 2020 में शुरू हुई थी। उस समय छोटे व्यापार पर महामारी और सम्बन्धित स्थितियों का दबाव रहा, जिसके कारण पैदा होने वाले हालात बेहतर नहीं हो सके थे। इसलिये योजना का प्रस्तावित विस्तार जरूरी हो गया है। ऋण देने की गतिविधि को दिसंबर, 2024 तक बढ़ाये जाने से औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी, रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाने के लिये ऋण मिलना सुनिश्चित हो जायेगा, डिजिटल भुगतान में इजाफा होगा, ऋण प्रदाता संस्थानों के फंसे हुये कर्ज के असर में कमी आयेगी तथा रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिजनों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। ■

भारत में बना 100वां यूनिकॉर्न

भारत के 100 यूनिकॉर्न का कुल मूल्य 332.7 अरब डॉलर है।
वर्ष 2022 के पहले चार महीनों के दौरान भारत में तैयार हुए 14 यूनिकॉर्न

भारत में यूनिकॉर्न की लहर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, क्योंकि देश ने 2 मई, 2022 को अपने 100वें यूनिकॉर्न का जन्म देखा। आज वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न का उदय भारत में हो रहा है। 'यूनिकॉर्न' उन दुर्लभ स्टार्टअप को कहा जाता है जो 1 बिलियन डॉलर से अधिक का मूल्यांकन हासिल कर लेता है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा छह मई को जारी एक बयान के अनुसार भारतीय स्टार्टअप परिवेश यूनिकॉर्न की संख्या के लिहाज से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यहां 5 मई, 2022 तक 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं जिनका कुल मूल्यांकन 332.7 अरब डॉलर है।

वर्ष 2021 के दौरान यूनिकॉर्न की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया था। इस दौरान कुल 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न 93 अरब डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए। वर्ष 2022 के पहले चार महीनों के दौरान भारत में 18.9 अरब डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ 14 यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं।

गौरतलब है कि स्टार्टअप इंडिया अभियान के शुभारंभ यानी 16 जनवरी, 2016 के बाद से 2 मई, 2022 तक देश में 69,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। भारत में नवाचार केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आईटी सेवाओं से 13 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान से 9 प्रतिशत, शिक्षा 7 प्रतिशत, पेशेवर एवं वाणिज्यिक सेवाओं से 5 प्रतिशत, कृषि 5 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थों से 5 प्रतिशत के साथ 56 विविध क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने वाले स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।

हालांकि, प्रत्येक स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न बनने की अपनी अनूठी यात्रा होती है, लेकिन भारत में स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने के लिए न्यूनतम समय 6 महीने और अधिकतम समय 26 वर्ष है। वित्त वर्ष 2016-17 तक हर साल लगभग एक यूनिकॉर्न तैयार होता था। पिछले चार वर्षों में (वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से) यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और हर साल अतिरिक्त यूनिकॉर्न की संख्या में सालाना आधार पर 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ■

खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटास (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनबीएस-खरीफ सीजन 2022 के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने डीएपी पर 1650 रुपये प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के स्थान पर 2501 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया, जो पिछले साल की सब्सिडी दरों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अप्रैल को खरीफ सीजन-2022 (01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटास (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

माल ढुलाई संबंधी सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक के लिए सहायता (एसएसपी) और डीएपी के स्वदेशी उत्पादन व आयात के लिए अतिरिक्त सहायता समेत मंत्रिमंडल द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) खरीफ-2022 (01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक) के लिए मंजूर की गई सब्सिडी 60,939.23 करोड़ रुपये होगी।

उल्लेखनीय है कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। केंद्र सरकार ने डीएपी पर 1650 रुपये प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के स्थान पर 2501 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है, जो पिछले साल की सब्सिडी दरों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। डीएपी और उसके कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे किसानों को रियायती, सस्ती और उचित दरों पर अधिसूचित पीएंडके उर्वरक प्राप्त करने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि सरकार उर्वरक उत्पादकों/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 25 ग्रेड पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। एनबीएस योजना द्वारा पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01 अप्रैल, 2010 से नियंत्रित की जा रही है। ■

हमारा हित

पं. दीनदयाल उपाध्याय

गतांक से...

हम कम्युनिस्टों और समाजवादियों की तरह समाज में वर्गों को स्वीकार करते हैं, पर इनकी तरह परस्पर वर्गों में मतभेद को स्वीकार नहीं करते। समाज में जो वर्ग विद्यमान हैं, वह कार्य की व्यवस्था या Division of Works के कारण है, ऐसा अपना वर्गों के प्रति दृष्टिकोण है। स्कूल में कई classes होती हैं। ये classes शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई कहे classes का यह classification संघर्ष के कारण है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि एक ही समाज में रहनेवाले वकील और डॉक्टर के बीच भी संघर्ष है। माता, पुत्र, पति-पत्नी, मालिक और मज़दूर के बीच में संघर्ष है। क्या यह सत्य है? मालिक और मज़दूर का स्वार्थ मिलने पर ही कोई कारखाना खड़ा होता है। किसी एक के स्वार्थ पर कारखाना खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मजदूर का interest और मालिक का interest अलग-अलग नहीं है। इस तरह मालिक और मज़दूर के बीच मतभेद को स्वीकार करना उचित नहीं। पश्चिम के लोग व्यक्ति और समाज में मतभेद स्वीकार करते हैं। राज्य व्यक्ति को गुलाम बना सकता है। पर पश्चिम के लोगों का यह कहना सरासर गलत है कि समाज व्यक्ति को गुलाम बनाता है। उसी तरह व्यक्ति और समाज में भी संघर्ष नहीं है। व्यक्ति का हित ही समाज का हित है। पेड़ और फूल में संघर्ष कहां है? पेड़ तो चाहता है, उसे फूल आए.. फल आए। पेड़, फल और फूल में संघर्ष नहीं है। क्या फल और फूल समझते हैं कि पेड़ हमें गुलाम बना रहा है? इसके साथ ही साथ क्या पेड़ यह सोचता है कि मैं फल और फूल को गुलाम बना रहा हूं? पेड़ का जीवन लक्ष्य ही है कि उसे फूल और फल आएं, उसी में उसके जीवन की सार्थकता है।

व्यक्ति और समाज एक है। व्यक्ति द्वारा समाज फलता और फूलता है, व्यक्ति समाज से हटकर अपना विकास नहीं कर सकता, इस तरह व्यक्ति और समाज का विकास परस्परावलंबित है

इसी तरह किसी का यह समझना समाज व्यक्ति को गुलाम बनाता है, भ्रामक और मिथ्या है। इसी तरह मां के जीवन का लक्ष्य बेटा सुखी और पढ़ा-लिखा हो, यही है। मां-बेटे के बीच संघर्ष नहीं रहा। मां यदि बच्चे को पढ़ने के लिए कहती है और कभी डांटती भी होगी तो वह मां-बेटे के बीच संघर्ष समझना, साथ ही साथ पुत्र का यह समझना कि मां मुझे गुलाम बना रही है, यह धारणा ग़लत है। बेटे को भी यह प्रतिकूल विचार नहीं आता, यदि इसे मां-बेटे के बीच स्थायी संघर्ष समझे। तो यह पश्चिम की देन है, जो सरासर ग़लत है।

व्यक्ति और समाज एक है। व्यक्ति द्वारा समाज फलता और फूलता है, व्यक्ति समाज से हटकर अपना विकास नहीं कर सकता, इस तरह व्यक्ति और समाज का विकास परस्परावलंबित है। हमारे बालों का सर के साथ घनिष्ठ संबंध है। बालों को काटकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर रोटी-पानी दीजिए, वे ख़राब हो जाएंगे पर बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब वे शरीर के साथ रहेंगे, तभी उनका विकास होगा। इसी तरह व्यक्ति को समाज से हटकर विचार नहीं करना चाहिए। जब केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार होगा, पर समाज और राष्ट्र का नहीं तो व्यक्तिगत स्वार्थ भी पूरा नहीं हो सकता। यदि कोई केवल मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, इसका विचार करेगा, पर राष्ट्र का नहीं, तो काम नहीं चलेगा। यदि कोई फल की अपेक्षा करे और पेड़ की ओर दुर्लक्ष करे तो फल प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह दूध की अपेक्षाकर गाय के पोषण का दुर्लक्ष होगा तो न दूध ही मिलेगा न गाय ही जीवित रहेगी। इसी प्रकार राष्ट्र समाज का चिंतन छोड़ केवल व्यक्ति अपना ही विचार करे तो न उसका विकास होगा, न समाज और राष्ट्र ही संवर्धित होगा।

समाज में उसी वर्ग के साथ लड़ाई या संघर्ष होगा, जो समाज में भेद उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। समाज में भेद उत्पन्न करना, यही विकृति होगी और वहां संघर्ष अटल है। हमारा संपूर्ण शरीर उसके भिन्न-भिन्न अवयव, भिन्न-भिन्न कार्य में संलग्न हैं, कार्य व्यवस्था का आदर्श नमूना है। विभिन्न अवयवों में जिनके कार्य एक दूसरे से अलग हैं, पर उनमें अपने कार्य के प्रति मतभेद दिखाई देता है क्या? यदि दाएं हाथ ने बाएं हाथ की चिंता छोड़ दी, उसी तरह शरीर का प्रत्येक अवयव एक-दूसरे से असंगत व्यवहार करेगा, तो शरीर का कार्य नहीं चल सकता। जब हाथ अपना काम, पैर अपना काम करे, तभी सभी कार्य समुचित रूप से चलेंगे। अवयवों में काम की भिन्नता व्यवस्था का अंग है। इस अलग-अलग कार्य को कोई संघर्ष या भेद

कैसे कह सकता है?

कार्य का बंटवारा (division of labour) विकसित जीवन का लक्ष्य है। सभी कार्य एक के द्वारा ही पूर्ण नहीं हो सकते, इसीलिए कार्य को उचित ढंग से पूर्ण करने के लिए विभिन्न वर्गों में बांटना कार्य की सफलता और उसकी निपुणता के लिए आवश्यक है। यदि इसी प्रकार के कार्य विभाजन से वर्गभेद उत्पन्न होगा तो वह ग़लत है। कार्य जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, कार्य विभाजन भी बढ़ता जाएगा। हम जो खाते हैं, वह शरीर में पहुंचकर भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है। यही भोजन मांस, खून, मज्जा, हड्डी, वीर्य बनता है। यदि किसी ने कहा कि मैं तो खाना खाता हूं, यह हड्डियां कैसे बनीं, यह तो अलग कार्य कर रहा है, यह तो विभेद है तो इस तरह की समझ भ्रममूलक है। वास्तव में भोजन द्वारा बने खून, हड्डी व वीर्य में विभेद न होकर विविधता है। विकृति उसे कहेंगे जब भोजन पेट में पहुंचकर खून बनने के बजाय उससे रक्त विरेचन हो रहा होगा। यह विकृति शरीर के लिए प्रतिकूल है, उसी तरह समाज की इस विविधता को विभेद मानकर चलेंगे तो वह विकृति है, जो समाज जीवन के प्रतिकूल है।

शरीर में दिखाई देनेवाली यह विभिन्नता विभेद के कारण न होकर व्यवस्था के कारण है, तभी एक ही शरीर पर आंखों का कार्य देखने का है, मुंह का कार्य बोलने का है, पैरों का कार्य चलने का है, यह विविधता जो वस्तुतः व्यवस्था है, शरीर के लिए आवश्यक है। उसी तरह हम जब भोजन करते हैं तो उसका खून बनना जरूरी है, कारण यह शरीर का शक्ति संस्थान है, इसी रक्त से शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव अपने कार्य के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि यही भोजन रक्त न होकर फोड़ा बनेगा तो यह विकृति होगी, जो शरीर के लिए घातक सिद्ध होगी। जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव हैं। एक ही रक्त से शक्ति प्राप्त कर कोई देखने का कार्य करता है तो कोई बोलने का, इसी तरह समाज-यह एक और उसकी शक्ति भी एक और उसके घटक अपने-अपने बल सामर्थ्य के अनुसार अलग-अलग कार्य करेंगे। जैसे कोई व्यापार करेगा, कोई कारखाना चलाएगा, कोई नौकरी करेगा पर कार्य की इस विभिन्नता के कारण संपूर्ण समाज को विभिन्न वर्गों में विघटित करेंगे तो यह भारी भूल होगी।

यह भूल समाज में विकृति उत्पन्न करेगी, जिसके कारण सारा समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जब कभी विचार करे, तब अपने को समाज व राष्ट्र से पृथक् रखकर न करे। यदि कोई राष्ट्र और समाज का विचार छोड़ केवल व्यक्तिगत विचार करेगा तो उसका विकास संभव नहीं है। समाज की समुचित कार्य व्यवस्था के लिए उपरोक्त विभाजन किया गया है। जो इस व्यवस्था को वर्ग मानकर उनमें संघर्ष है, समझकर चलते हैं। वास्तव में उन्होंने समाज को समझने का प्रयत्न नहीं किया। हमारा समाज जीवन विविध रूप में प्रकट हुआ है, विविधता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। विविधता समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती है। ■

समाप्त

-संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : आंध्र प्रदेश, 16 मई, 1965

प्रधानमंत्री ने प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल को मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 'भारत रत्न' लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाएगा।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत के इस सामर्थ्य और शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए, लता दीदी 'सुर साम्राज्ञी' होने के साथ-साथ मेरी बड़ी बहन भी थीं। पीढ़ियों को प्रेम और भावनाओं का उपहार देने वाली लता दीदी से अपनी बहन जैसा प्यार पाने से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।

श्री मोदी ने कहा कि वे आमतौर पर पुरस्कार लेते हुए बहुत सहज नहीं महसूस करते, लेकिन जब मंगेशकर परिवार लता दीदी जैसी बड़ी बहन का नाम लेता है और उनके नाम पर पुरस्कार देता है, तो यह उनके स्नेह और प्यार का प्रतीक बन जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इसे ना कहना संभव नहीं है। मैं यह पुरस्कार सभी देशवासियों को समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी लोगों की थीं, वैसे ही उनके नाम पर मुझे दिया गया यह पुरस्कार भी लोगों का है।

श्री मोदी ने कई व्यक्तिगत किस्से सुनाए और सांस्कृतिक जगत में लता दीदी के असीम योगदान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लता जी की जीवन यात्रा ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी से पहले भारत को आवाज दी थी और देश की इन 75 वर्षों की यात्रा भी उनकी आवाज के साथ जुड़ी रही। ■

कुशल राजनेता के. जना कृष्णमूर्ति

(24 मई, 1928 - 25 सितंबर, 2007)

शत-शत नमन

श्री के. जना कृष्णमूर्ति भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रखर राष्ट्रप्रेमी और कुशल राजनेता थे। वे 2001 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। श्री जना कृष्णमूर्ति श्री कामराज के बाद तमिलनाडु से आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व किया।

श्री कृष्णमूर्ति का जन्म 24 मई, 1928 को तमिलनाडु राज्य के मदुरई में हुआ। उनके पिता और माता का नाम श्री कृष्णास्वामी और श्रीमती सुब्बलक्ष्मी था। 26 अगस्त, 1964 को उनका विवाह भाग्यलक्ष्मी से हुआ। उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने 1965 में सफल वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर की प्रेरणा से राष्ट्रसेवा का व्रत लिया। दरअसल, श्री कृष्णमूर्ति 1940 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश पर उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनसंघ के महामंत्री का कार्य भार संभाला। सच तो यह है कि श्री कृष्णमूर्ति दक्षिण भारत में भारतीय जन संघ को मजबूत और विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1975 में जब आपातकाल घोषित हुआ, तो उस समय वह तमिलनाडु में रेजिस्टेंट मूवमेंट के सचिव थे। 1977 में जब भारतीय जन संघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, तब वह पार्टी की तमिलनाडु इकाई में महामंत्री बने। उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय मंत्री थे। 1983 में वे राष्ट्रीय महामंत्री बने और 1985 में वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। 1980 से 1990 के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के चार राज्यों जैसे— केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भाजपा के विस्तार में अतुलनीय योगदान दिया।

1993 में श्री लालकृष्ण आडवाणी के अनुरोध पर वे दिल्ली आ गए और भाजपा में आर्थिक, रक्षा और विदेशी मामलों पर बौद्धिक प्रकोष्ठ की स्थापना की। 1995 में वे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय के प्रभारी बने। उन्होंने पार्टी प्रवक्ता पद को भी सुशोभित किया। 14 मार्च, 2001 को वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जून, 2002 तक वे इस पद पर रहे। इसके साथ ही श्री जना कृष्णमूर्ति अप्रैल, 2002 में राज्य सभा के सदस्य बने और 2002-2003 तक केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे। 25 सितबंर, 2007 को श्री जना कृष्णमूर्ति का देहावसान हो गया। राष्ट्र और भाजपा इनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ है। ■

1993 में श्री लालकृष्ण आडवाणी के अनुरोध पर वे दिल्ली आ गए और भाजपा में आर्थिक, रक्षा और विदेशी मामलों पर बौद्धिक प्रकोष्ठ की स्थापना की। 1995 में वे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय के प्रभारी बने। उन्होंने पार्टी प्रवक्ता पद को भी सुशोभित किया। 14 मार्च, 2001 को वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जून, 2002 तक वे इस पद पर रहे। इसके साथ ही श्री जना कृष्णमूर्ति अप्रैल, 2002 में राज्य सभा के सदस्य बने और 2002-2003 तक केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे। 25 सितबंर, 2007 को श्री जना कृष्णमूर्ति का देहावसान हो गया। राष्ट्र और भाजपा इनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ है

असम में सात कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित

असम में कैंसर अस्पतालों से पूर्वोत्तर के साथ-साथ दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य सेवा की क्षमता में वृद्धि होगी: नरेन्द्र मोदी

सरकार कई दवाओं की लागत को लगभग आधा करके कैंसर की दवाओं को सस्ती कर रही है, जिससे रोगियों को कम से कम 1000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है

गत 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में एक समारोह में असम के सात कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये कैंसर अस्पताल डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में बने हैं। डिब्रूगढ़ अस्पताल को प्रधानमंत्री द्वारा दिन में पहले ही राष्ट्र को समर्पित किया गया, जब उन्होंने नए अस्पताल के परिसर का दौरा किया।

श्री मोदी ने परियोजना के दूसरे चरण में बनाए जाने वाले धुबरी, नलबाड़ी, गोलपारा, नगांव, शिवसागर, तिनसुकिया और गोलाघाट में सात नए कैंसर अस्पतालों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री रामेश्वर तेली, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य श्री रंजन गोगोई और प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा उपस्थित लोगों में शामिल थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने त्योहारी सीजन के उत्साह का वर्णन करते हुए अपना भाषण शुरू किया और असम के महान सपूतों और पुत्रियों को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि असम में कैंसर अस्पताल जो आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं और जिनकी आज आधारशिला रखी गई है, पूर्वोत्तर के साथ-साथ दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य सेवा की क्षमता में वृद्धि करेंगे।

यह स्वीकार करते हुए कि असम ही नहीं नॉर्थ-ईस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारा गरीब होता है, मध्यम वर्ग का परिवार होता है। कैंसर के इलाज के लिए कुछ साल पहले तक यहां के मरीजों को बड़े-बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ता था।

श्री मोदी ने कहा कि असम में गरीब और मिडिल क्लास की इस परेशानी को दूर करने के लिए बीते 5-6 सालों से जो कदम उठाए गए हैं, उसके लिए मैं सर्बानंद सोनोवाल जी, हेमंता जी और टाटा ट्रस्ट को बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में 1500 करोड़ रुपये की योजना— प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल (पीएम-डिवाइन) की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत भी कैंसर के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और गुवाहाटी में भी इसी तरह की सुविधाएं प्रस्तावित हैं।

श्री मोदी ने कहा कि कैंसर के इलाज पर अत्यधिक खर्च लोगों के मन में सबसे बड़ी चिंता थी। महिलाओं ने विशेष रूप से इस इलाज से परहेज किया, क्योंकि इसमें परिवार को कर्ज और दरिद्रता में धकेलने की क्षमता थी। सरकार कई दवाओं की लागत को लगभग आधा करके कैंसर की दवाओं को सस्ती कर रही है, जिससे रोगियों को कम से कम 1000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। जन औषधि केंद्रों में अब 900 से अधिक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत बहुत से लाभार्थी कैंसर के रोगी हैं।

उन्होंने कहा कि 'आयुष्मान भारत' और वेलनेस सेंटर कैंसर के मामलों का जल्द पता लगाना सुनिश्चित कर रहे हैं। असम और देश के अन्य हिस्सों में वेलनेस सेंटरों में 15 करोड़ से अधिक लोगों ने कैंसर की जांच कराई है। श्री मोदी ने राज्य में बुनियादी चिकित्सा सुविधा में सुधार के लिए असम सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि असम सरकार और टाटा ट्रस्ट्स का एक संयुक्त उद्यम— असम कैंसर केयर फाउंडेशन, राज्य भर में फैले 17 कैंसर सेवा अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा किफायती कैंसर सेवा का नेटवर्क बनाने के लिए एक परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना के पहले चरण में 10 अस्पतालों में से सात अस्पतालों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि तीन अस्पताल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजना के दूसरे चरण में सात नए कैंसर अस्पतालों का निर्माण होगा। ■

'हर छोटा एवं बड़ा व्यवसाय राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे रहा है'

केंद्र सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि सामान्य परिवारों के युवा भी उद्यमी बन सकें और उसके लिए सपने देख सकें व अपनी उद्यमिता पर गर्व कर सकें

गत 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदारधाम द्वारा आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, कई केन्द्रीय मंत्री और उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां मौजूद थीं।

इस अवसर पर श्री मोदी ने सूरत शहर को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक के रूप में रेखांकित किया। सरदार पटेल के कथन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत के पास इतना कुछ है। "हमें बस अपने आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के जज्बे को मजबूत करना है। यह आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबका प्रयास लगेगा।"

देश में उद्यमिता की भावना को बढ़ाने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि अपनी नीतियों, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य परिवार के युवा भी उद्यमी बनें, उसके लिए सपने देखें और अपनी उद्यमिता पर गर्व करें।

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है, जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। इसी तरह, 'स्टार्ट अप इंडिया' से वो इनोवेशन, वो टैलेंट भी आज यूनिकॉर्न के सपने को साकार होते देख रहा है, जिसको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था।

श्री मोदी ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पारंपरिक क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार तो कर ही रहा है, नए क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश का एमएसएमई क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है। बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता से इस क्षेत्र में लाखों रोजगार सुरक्षित हुए और अब यह क्षेत्र रोजगार के कई नए अवसर सृजित कर रहा है। पीएम-स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सुविधा प्रदान करके विकास की कहानी में शामिल किया है। श्री मोदी ने बताया कि इस योजना को हाल ही में दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर छोटा एवं बड़ा व्यवसाय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है और 'सबका प्रयास' की यही भावना अमृत काल में नए भारत की ताकत बन रही है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा हो रही है।

> **कृषि के नए तरीकों और नई फसलों के बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से गुजरात की भूमि का अध्ययन करने के लिए टीमें गठित की जा सकती हैं। श्री मोदी ने कुछ दशक पहले गुजरात में डेयरी आंदोलन की अवधारणा को अपनाए जाने का उदाहरण दिया, जिसने गुजरात के किसानों के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया**

श्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों से कृषि के आधुनिकीकरण और कृषि में निवेश लाने के तरीकों का पता लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि के नए तरीकों और नई फसलों के बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से गुजरात की भूमि का अध्ययन करने के लिए टीमें गठित की जा सकती हैं। श्री मोदी ने कुछ दशक पहले गुजरात में डेयरी आंदोलन की अवधारणा को अपनाए जाने का उदाहरण दिया, जिसने गुजरात के किसानों के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया।

उन्होंने कहा कि हमें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के तरीके खोजने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से खाद्य तेल के आयात को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की व्यापक संभावनाओं पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने उपस्थित जनसमुदाय से उभरते हुए एफपीओ की ओर देखने के लिए भी कहा, क्योंकि इन संगठनों के उभार के साथ कई अवसर भी खुल रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम करने को भी कहा। श्री मोदी ने खेतों में अतिरिक्त जगहों का उपयोग सौर पैनल के लिए करने की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से हाल ही में शुरू किए गए अमृत सरोवर अभियान में योगदान देने के लिए कहा। हाल ही में आयोजित आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर्बल और आयुष क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। ■

'हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का माध्यम संस्कृत ही है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 मई, 2022 को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित उत्कर्ष महोत्सव का शुभारंभ किया। विदित हो कि संस्कृत के तीनों विश्वविद्यालयों- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (नई दिल्ली), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (तिरुपति) की ओर से संयुक्त रूप से 'उत्कर्ष महोत्सव' का आयोजन किया गया। उत्कर्ष महोत्सव का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार और संवर्धन करना है, जिसकी विषय वस्तु 'नए शैक्षिक युग में संस्कृत अध्ययन का वैश्विक उन्मुखीकरण' रखी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, नालंदा विश्वविद्यालय (नालंदा) के कुलाधिपति डॉ. विजय भाटकर, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (तिरुपति) के कुलपति प्रो. राधाकांत ठाकुर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) के कुलपति प्रो. मुरलीमनोहर पाठक, आर्थिक परामर्श परिषद् के अध्यक्ष श्री बिबेक देबरॉय और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (तिरुपति) के कुलसचिव श्री चलावेंकटेश्वर भी उपस्थित थे।

> **जहां संस्कृत है, वहीं संस्कृति है और वही हमारी विचारधारा भी है। संस्कृति के साथ-साथ यह विकास का भी माध्यम है। संस्कृत देवभाषा और अमृत वाणी है**

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जहां संस्कृत है, वहीं संस्कृति है और वही हमारी विचारधारा भी है। संस्कृति के साथ-साथ यह विकास का भी माध्यम है। संस्कृत देवभाषा और अमृत वाणी है। हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का माध्यम संस्कृत ही है। सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद भी संस्कृत में ही है। हम सब अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध भाव से काम कर रही है। हम संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं। भारत की पुरातन परंपरा और महान संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। यह निश्चित रूप से संस्कृत और संस्कृति के संवर्धन के लिए सबसे अच्छा काल है। ऐसा काल सदैव बना रहे, यह आप सब की, हम सभी देशवासियों की जिम्मेवारी है।

श्री नड्डा ने कहा कि विदेशों में लोग कहते रहते हैं कि - गिव मी स्पेस, गिव मी स्पेस जबकि भारत में लोकल बसों और ट्रेन में देख लीजिये कि कैसे हजारों लोग एक साथ आत्मीय भाव से सफ़र करते हैं, मिलजुल कर चलते हैं। यही हमारी संस्कृति है जो 135 करोड़ देशवासियों को एक साथ जोड़े रखती है। सहनशीलता, सहिष्णुता, सबकी बातें सुनना, सत्य की खोज के लिए विपक्ष की बात भी गहराई से सुनना - यही हमारी संस्कृति की पहचान है। दूसरे पक्ष को रखने वाले लोग अपने ही समाज में मिलते हैं। यह है सोचने की संस्कृति का संचार। यही तो भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (नई दिल्ली), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (तिरुपति), तीनों संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन विश्वविद्यालयों को क्यों पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर मंच पर संस्कृत की महत्ता को स्थापित किया है। जब नीयत साफ़ हो तो नीति भी स्पष्ट होती है और उन नीतियों को जमीन पर लागू करने वाले आप जैसे मनीषी ही हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, उनके नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, भाजपा और हम सब संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कटिबद्ध हैं। ■

'आत्मनिर्भर भारत' हमारा रास्ता भी है और संकल्प भीः नरेन्द्र मोदी

भारत अब 'संभावना और क्षमता' से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक कल्याण के एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही, आज देश प्रतिभा, कारोबार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रहा है

गत छह मई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के 'जीतो कनेक्ट 2022' के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम की थीम में 'सबका प्रयास' की भावना का उल्लेख किया और कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। वैश्विक शांति हो, वैश्विक समृद्धि हो, वैश्विक चुनौतियों से संबंधित समाधान हों या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सशक्तिकरण हो, दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है।

उन्होंने कहा कि मैं कई यूरोपीय देशों को 'अमृत काल' के लिए भारत के संकल्प के बारे में जानकारी देने के बाद अभी-अभी वापस आया हूं। श्री मोदी ने कहा कि विशेषज्ञता का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र चाहे जो भी हो, विचारों में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन नए भारत का उदय सभी को जोड़ता है। आज सभी को लगता है कि भारत अब 'संभावना और क्षमता' से आगे बढ़कर वैश्विक कल्याण के एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है।

सही उद्देश्य, स्पष्ट इरादा और अनुकूल नीतियों से जुड़ी अपनी बातों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आज देश; जितना संभव हो सकता है; प्रतिभा, कारोबार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश प्रतिदिन दर्जनों स्टार्टअप का पंजीकरण कर रहा है, प्रति सप्ताह एक यूनिकॉर्न बना रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि जब से सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी जीईएम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद सबके सामने एक प्लेटफॉर्म पर होती है। अब दूरदराज के गांवों के लोग, छोटे दुकानदार और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे सरकार को बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज जीईएम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक विक्रेता जुड़ चुके हैं। उन्होंने पारदर्शी 'फेसलेस' टैक्स निर्धारण, एक राष्ट्र-एक टैक्स, उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी बात की।

श्री मोदी ने कहा कि भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट हैं। "आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और संकल्प भी। बीते सालों में हमने इसके लिए हर ज़रूरी माहौल बनाने में निरंतर परिश्रम किया है।"

प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय से 'ईएआरटीएच–अर्थ' के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि 'ई' का अर्थ है; एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की समृद्धि। श्री मोदी ने उनसे इस पर भी चर्चा करने का आग्रह किया कि वे अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने के प्रयासों को कैसे समर्थन कर सकते हैं। 'ए' का अर्थ है; एग्रीकल्चर, यानी कृषि को अधिक लाभकारी बनाना और प्राकृतिक खेती, कृषि प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करना। 'आर' का अर्थ है; रीसाईकल यानी पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर देना, पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए काम करना। 'टी' का अर्थ है; टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाना।

उन्होंने लोगों से इस बात पर विचार करने का आग्रह किया कि वे ड्रोन तकनीक जैसी अन्य उन्नत तकनीक को और अधिक सुलभ कैसे बना सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 'एच' का अर्थ है; हेल्थकेयर, यानी स्वास्थ्य देखभाल। उन्होंने कहा कि आज सरकार देश के हर जिले में स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्थाओं के लिए बहुत काम कर रही है। उन्होंने जनसमुदाय से इस बात पर भी विचार करने का आग्रह किया कि उनकी संस्था इसे कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ■

भारत ने अपनी 85 प्रतिशत पात्र आबादी का कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण किया

भारत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला रहा है। इस दौरान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासन और अन्य हितधारकों ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया लेकिन इसके बावजूद हमने इस टीकाकरण अभियान के दौरान कई मील के पत्थर हासिल किये हैं और कुछ सबसे कठिन इलाकों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को चलाया। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप अब तक देश की 96 प्रतिशत वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। ऐसे ही 15 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र 85 प्रतिशत आबादी को दूसरी खुराक दी जा चुकी है।

इन प्रयासों और हमारी इच्छाशक्ति के कारण देश में कोविड-19 वैक्सीन खुराकों की संचयी संख्या 7 मई को 190 करोड़ को पार कर गई है। अब तक, 12-14 वर्ष की आयु के 3.01 करोड़ (3,01,97,120) से अधिक बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 2.63 बिलियन से अधिक एहतियाती खुराक दी गई है।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2017 को शुरू हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों का सबसे पहले टीकाकरण किया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण पिछले साल 2 फरवरी से शुरू हुआ था।

कोविड-19 टीकाकरण अभियान का अगला चरण पिछले साल 1 मार्च को आरंभ हुआ जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ जो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे। पिछले साल 1 अप्रैल से भारत ने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया।

पिछले साल 1 मई से सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति का टीकाकरण करने की अनुमति देकर इस टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने का निर्णय लिया।

टीकाकरण का अगला चरण 3 जनवरी से आरंभ हुआ, जिसमें 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों का टीकाकरण किया गया।

भारत ने 10 जनवरी से स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को एहतियाती खुराक देना शुरू किया। देश ने 16 मार्च से 12-14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को एहतियाती खुराक देने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हमें अभी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि महामारी से संबंधित चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।

उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण करना है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में भी विशेष अभियान चलाने की जरूरत होगी। शिक्षकों और अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए।" इस बीमारी के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए देश के सभी वयस्कों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षक, माता-पिता और अन्य पात्र लोग एहतियाती खुराक ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96 फीसदी वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल गई है, जबकि 15 साल से अधिक उम्र की 85 फीसदी योग्य आबादी को दूसरी खुराक दी जा चुकी है।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत के सफल कोविड-19 प्रबंधन और टीकाकरण अभियान का अध्ययन दुनिया भर के विशेषज्ञ कर रहे हैं और भारत ने दुनिया को एक व्यापक स्वास्थ्य मॉडल प्रदान किया है।

"भारत 1.3 बिलियन लोगों की आबादी और विविध संस्कृति वाला एक बड़ा देश है।" ऐसे में 97.5 फीसदी जनता को वैक्सीन की पहली खुराक देना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के इस मॉडल को सारी दुनिया देख रही है। आज भारत को किसी वैश्विक मॉडल को अपनाने की अवश्यकता नहीं है। बल्कि आज भारत ने भी दुनिया के सामने अपना मॉडल पेश किया है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। आज, दुनिया भर के विशेषज्ञ देश के कोविड-19 प्रबंधन और टीकाकरण अभियान का अध्ययन करने के लिए भारत आ रहे हैं और हमें आने वाले दिनों में इसको लेकर और अधिक प्रयास जारी रखने है। ■

देश भर के किसान मोदीजी के साथ हैं: राजकुमार चाहर

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद श्री राजकुमार चाहर ने कमल संदेश के सह-संपादक राम प्रसाद त्रिपाठी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में 2014 में मोदी सरकार बनाने के बाद किसानों और कृषि क्षेत्र के समर्थन में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों और सरकार की उपलब्धियों पर बातचीत की।

श्री चाहर ने भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रव्यापी गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि कैसे मोर्चा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जागरुकता फैलाने का कार्य कर रहा है, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है और यह उनके सर्वांगीण विकास में सहायक बन रहा है। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंशः

मोदी सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये योजनाएं क्या हैं और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप इन कदमों को कैसे देखते हैं?

किसान सशक्तीकरण के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है और इस संकल्प के अनुरूप देश ने किसान हितैषी मोदी सरकार को पिछले आठ वर्षों में किसानों को आत्मनिर्भर बनाते देखा और यह प्रयास निरंतर जारी है। जमीनी स्तर पर किसानों को सशक्त बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रति वर्ष लाभार्थियों के बैंक खाते में 6,000 रुपये स्थानांतरित किए जाते हैं और अब तक लगभग 11.3 करोड़ किसानों को लगभग 1.83 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। खेती के लिए सबसे कठिन दौर में भी मोदी सरकार ने यह आर्थिक मदद किसानों को दी और उनको राहत पहुंचाने का काम किया, यही कारण है कि इस कठिन दौर में हमारे किसान कर्ज के चंगुल में नहीं फंसे।

इसी तरह, प्रधानमंत्री ने हमारी पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। वर्ष 2019 से उन्होंने देश भर के किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील की है, जिससे कम लागत में अधिक लाभ होता है। इस अभियान में लाखों किसान शामिल हुए और आज उन्हें जैविक खेती से भारी लाभ मिल रहा है। यह पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि सिक्किम जैसे राज्य ने जैविक खेती को अपनाया और अब यह दुनिया का पहला राज्य है जो 100 प्रतिशत जैविक खेती करता है।

इसी तरह किसान की आय को दोगुना करने के लिए और एक मजबूत कृषि बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने 'एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' बनाया और फार्म-गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई। अब तक लगभग 11,632 परियोजनाओं के लिए लगभग 8,585 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देने, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संवाद विषमता को दूर करने और वास्तविक मांग एवं आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य निर्धारण के लिए मोदी सरकार ने 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (ई-नाम) लॉन्च किया है। यह सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस योजना के तहत लगभग 1.73 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया गया है और इस मंच ने अब तक लगभग 1.87 लाख करोड़ का कारोबार किया है।

इन बड़ी योजनाओं के अलावा, सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं।

कल्याणकारी उपाय किसान की आय को कैसे दोगुना कर रहे हैं?

शायद आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को स्थिर बनाने की पहल की है। किसान की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए और जिनके परिणाम शानदार रहे।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'- फसल बीमा से लेकर किसानों के लिए छोटे ऋण की व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रौद्योगिकी प्रदान करना, विपणन सहायता, गन्ना और अन्य किसानों के लिए हजारों करोड़ की सब्सिडी, लगभग सभी कृषि उत्पादों के एमएसपी में वृद्धि, जैविक खाद को बढ़ावा देना और

स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने तक, मोदी सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए अविश्वसनीय काम किया है। सरकार के इन प्रमुखों कदमों ने देश के हर किसान, मछुआरे और पशुपालक आदि का भविष्य सुरक्षित किया है, साथ ही यह कदम किसान की आय को दोगुना करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे है।

मोदी सरकार की कृषि नीतियां पिछली सरकारों की तुलना में कैसे अलग हैं?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन से जीडीपी बढ़ सकती है और अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो भारत की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए, सरकार जो भी कदम उठा रही है, वह हमारे कृषक समुदाय को मजबूत करने के लिए है। यह मोदी सरकार और पिछली सरकारों के बीच प्रमुख नीतिगत अंतर है।

उदाहरण के लिए जब प्रधानमंत्री श्री मोदी सत्ता में आए, तो गन्ने की दर 2300 रुपये प्रति क्विंटल थी, और दो साल से अधिक समय से भुगतान बकाया था। लेकिन, आज पूरा भुगतान कर दिया गया है और इस अवधि के दौरान किसानों के उत्पादन और भुगतान दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यूपीए सरकार के दौरान ब्राजील से गन्ना आयात किया जाता था, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो उसने 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया और किसानों को प्रोत्साहन देकर गन्ने के निर्यात को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप गन्ने का अधिशेष उत्पादन और रिकॉर्ड उच्च निर्यात संभव हुआ।

> प्राकृतिक खेती अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसान मोर्चा ने बिहार के पटना में गंगा के तट पर एक पदयात्रा शुरू की। इस दौरान हजारों किसान भाइयों और बहनों ने इसमें भाग लिया और जैविक खेती करने का संकल्प लिया। जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए हमने आने वाले दिनों में इस अभियान का विस्तार देश भर में करने का संकल्प लिया है

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान इथेनॉल उत्पादन प्रति वर्ष 38 करोड़ लीटर था, लेकिन अब यह 400 करोड़ लीटर है। मोदी सरकार ने चीनी मिलों को 4500 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन पैकेज प्रदान किया और अधिकांश मिलों ने इथेनॉल का उत्पादन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का लक्ष्य 2025 तक डीजल में कम से कम 20 प्रतिशत इथेनॉल शामिल करना है। इस कदम से गन्ना किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, पेट्रोल का आयात कम होगा और पर्यावरण को बचाया जा सकेगा।

इसी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश के लाखों गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों की स्थापना और कृषि-लॉजिस्टिक्स में निवेश और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना या हर गांव को डिजिटल हाईवे से जोड़ना भी महत्वपूर्ण कदम हैं जो इस सरकार को अलग बनाती है।

यूपीए के समय में देश का कृषि बजट केवल 29,000 करोड़ था। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कृषि बजट 1,35,000 करोड़ रुपये हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार लगातार किसानों और गांवों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

विपक्षी दल किसानों के वेश में राजनीति कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। हालांकि, 'किसान की सरकार-मोदी सरकार' हमारे किसान भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए अथक कार्य कर रही है। इसलिए देश भर के सभी किसान आज मोदी जी के साथ हैं।

आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद किसान मोर्चा की प्रमुख गतिविधियों के बारे में बताएं।

हाल में भाजपा ने अपने 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'सामाजिक न्याय पखवाड़ा' बनाया है, जिसके हिस्से के रूप में किसान मोर्चा ने देश भर के किसानों के साथ बैठकें आयोजित की है। इन कार्यक्रमों के दौरान मोर्चा कार्यकर्ता किसानों के बीच गए और उनको सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत करवाया।

हाल ही में, प्राकृतिक खेती अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसान मोर्चा ने बिहार के पटना में गंगा के तट पर एक पदयात्रा शुरू की। इस दौरान हजारों किसान भाइयों और बहनों ने इसमें भाग लिया और जैविक खेती करने का संकल्प लिया। जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए हमने आने वाले दिनों में इस अभियान का विस्तार देश भर में करने का संकल्प लिया है। इसी तरह, मोर्चा ने राजस्थान में किसान लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया, केरल के कोच्चि में एक विशाल किसान-महासंगम का आयोजन किया, पंजाब में आप सरकार के खिलाफ बठिंडा आदि में किसानों की आत्महत्या का विरोध किया।

मोर्चा ने 'किसानों की बात—किसानों के साथ', 'मोदीजी की मन की बात—गांव में सुनेंगे किसानों के साथ' जैसे अभिनव कार्यक्रम भी शुरू किए, 'सेवा ही संगठन' कार्यक्रम के तहत किसान मोर्चा ने कोविड-19 के दौरान लाखों लोगों की मदद की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन 'किसान-जवान सम्मान दिवस' के रूप में मनाया गया, 'ट्रैक्टर पूजन— किसान ट्रैक्टर रैली' के साथ ही देश के सभी राज्यों में किसानों के सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आगामी दिनों में मोर्चा हर गांव में अपने संगठन को मजबूत करेगा और 'आत्मनिर्भर कृषि' के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से प्रयास करेगा। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण नीति निर्धारक के रूप में उभरा

विकास आनन्द

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हाल ही में यूरोप की यात्रा से लौटे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। बर्लिन में छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श में भाग लेने के अलावा श्री मोदी ने डेनमार्क का दौरा भी किया और पेरिस जाने से पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अपने मेजबान फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले कोपेनहेगन में डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और नॉर्वे के नेताओं से भी मुलाकात की।

'मोदी युग' में यूरोप और भारत के संबंध एक बदलते परिदृश्य का गवाह बने हैं और यूरोपीय देश भारत के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की यह निकटता महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और विदेशी धरती पर रहने वाले भारतीयों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। वे अब अमेरिका के बजाय यूरोप को पसंद कर रहे हैं, जो इनके बीच यूरोपीय संघ के ब्लू कार्ड को प्राप्त करने की चाहत से बयान होता है।

'मोदी युग' में यूरोप और भारत के संबंध एक बदलते परिदृश्य का गवाह बने है और यूरोपीय देश भारत के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की यह निकटता महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और विदेशी धरती पर रहने वाले भारतीयों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है

भारत-यूरोपीय संघ के रिश्तो के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा, "भारतीयों को सबसे अधिक ईयू ब्लू कार्ड प्राप्त हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य यूरोप में अत्यधिक कुशल पेशेवरों को आकर्षित करना है। जर्मनी ने यूरोपीय संघ के भीतर सबसे बड़ी संख्या में ब्लू कार्ड जारी किए हैं और इनमें से एक चौथाई से अधिक कार्ड भारतीयों को जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत और फ्रांस भी प्रवास और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। दोनों देशों ने प्रवास और गतिशीलता पर साझेदारी समझौते को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखायी है, जो 1 अक्टूबर, 2021 को अमल में आया। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यात्रा के दौरान जर्मनी ने 'व्यापक प्रवास और गतिशीलता साझेदारी पर समझौते की शुरुआत पर भी हस्ताक्षर किए। इन उपायों से भारत और यूरोपीय देशों के नागरिकों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिक्षा, संस्कृति, गतिशीलता और पर्यटन के माध्यम से नागरिको के बीच मजबूत संपर्कों पर भी जोर दिया गया।

भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत पर्यावरण की कीमत पर अपना विकास नहीं चाहता है। इसलिए मोदी सरकार स्वच्छ ऊर्जा संचालित विकास पर जोर देती है। यह यात्रा हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सहयोग की गवाह बनी। कॉप-21 में संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू करने के सात वर्षों के बाद भारत और फ्रांस की जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। चूंकि अक्षय ऊर्जा आधारित विकास एक महत्वपूर्ण समाधान है, इसलिए भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना निरंतर समर्थन जारी रखने की बात कही है। दोनों ने नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन एवं सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच में बनाने के लिए जी—7 के माध्यम से ऊर्जा विकल्पों पर गौर करने पर भी सहमति व्यक्त की।

स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए भारत ने अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने की पहल में शामिल होने के लिए फ्रांस को आमंत्रित किया। दोनों पक्ष मजबूत औद्योगिक साझेदारी बनाने के लिए हाइड्रोजन के विनियमन, प्रमाणन और मानकीकरण से संबंधित पहलुओं सहित डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं और इस सहयोग को जल्द ही आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के साथ एशियाई और यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक साझेदारी स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे। जर्मनी के साथ, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में विकास और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत की

भारत और यूरोपीय संघ के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं का राजनीतिक-स्तरीय प्रबंधन करने तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय व्यापार एवं प्रौद्योगिकी आयोग स्थापित करने पर सहमति बनी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अप्रैल को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम उर्सुला वॉन डेर लेयेन की अगवानी की। श्री मोदी ने इस साल रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण देने के लिए सहमति प्रदान करने पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का धन्यवाद किया और कहा कि वे आज दिन में उनका संबोधन सुनने के लिए उत्सुक हैं।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि एक बड़े और जीवंत लोकतांत्रिक समाज के रूप में भारत तथा यूरोप विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर एक जैसे मूल्य और साझा दृष्टिकोण रखते हैं।

दोनों नेताओं ने एक मुक्त व्यापार समझौते एवं निवेश समझौते पर वार्ता की पुनः शुरुआत सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। भारत और यूरोपीय संघ के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं का राजनीतिक-स्तरीय प्रबंधन करने तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय व्यापार एवं प्रौद्योगिकी आयोग स्थापित करने पर सहमति बनी।

दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की संभावनाओं सहित जलवायु संबंधी विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 की निरंतर चुनौतियों पर भी चर्चा की और दुनिया के सभी हिस्सों में टीकों एवं चिकित्सा विज्ञान की समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर जोर दिया।

इसके अलावा, इस बैठक के दौरान यूक्रेन की स्थिति और भारत-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों सहित सामयिक महत्व के कई भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। ■

को रेखांकित किया और पूर्व-औद्योगिक स्तरों से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को जारी रखने की बात कही, जिससे अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। डेनमार्क में प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन और श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से अपतटीय पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में सहयोग पर सहमति बनी।

भारत और नॉर्डिक देशों ने भी जलवायु परिवर्तन को लेकर सहयोग को गहरा करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री की यात्रा 'आत्मनिर्भर भारत' की प्रगति का भी गवाह बनी। इसके तहत मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और फ्रांस के नेवल ग्रुप की सझेदारी में पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। मुंबई में एमडीएल में निर्मित छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस हद तक "मेक इन इंडिया" पहल के अनुरूप फ्रांस से भारत में प्रौद्योगिकी स्थानांतरित की गई है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों पक्ष 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम में फ्रांस की गहरी भागीदारी के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पर सहमत हुए, जिसके माध्यम से उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और निर्यात के साथ-साथ औद्योगिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की बात शामिल है।

भारत और यूरोपीय देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानवाधिकार जैसे विषयों पर विचारों को साझा किया, इसके साथ ही वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में बहुपक्षीय प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की। जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भारत की भूमिका उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है।

जेएनयू में अध्ययापन कर रहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार प्रोफेसर शक्ति प्रसाद श्रीचंदन कहते हैं, " यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ इंडो पैसिफिक में सुरक्षा शक्तियों के रूप में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अन्य समान विचारधारा वाली क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के साथ भू-रणनीतिक "बोझ साझाकरण" चाहते हैं। उनके लिए मूल्यों और हितों में समानता के कारण भारत एक विश्वसनीय क्षेत्रीय भागीदार के रूप में उभरा है। भारत की विदेश नीति में यूरोप पर मोदी सरकार का बढ़ता जोर भी इंडो पैसिफिक की ओर इस झुकाव को और मजबूत कर रहा है।

यूक्रेन संकट पर अलग रुख भारत की गहरी होती दोस्ती और यूरोपीय देशों के साथ जुड़ाव के आड़े नहीं आ सकी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राजनयिक कौशल और नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के प्रयास भारत को अन्य राष्ट्रों के करीब लाता हैं, जो भारत को नीति निर्धारक के तौर पर स्थापित करता हैं। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना' पर संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति दी

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ अब कुल परिव्यय 2,255 करोड़ रुपये

गत 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

इस परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक की स्थापना; बैंकिंग की सुविधा से वंचित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करके और घरों तक बैंकिंग की सुविधा के जरिए बैंकिंग की अपेक्षाकृत कम सुविधा पाने वाले लोगों के लिए अवसर संबंधी लागत को कम करके वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह परियोजना भारत सरकार के 'कम नकदी' वाली अर्थव्यवस्था से संबंधित दृष्टिकोण के पूरक है और साथ ही, आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन दोनों को बढ़ावा देती है।

भारतीय डाक भुगतान बैंक का 1 सितंबर, 2018 को 650 शाखाओं/नियंत्रण कार्यालयों के साथ देश भर में एक साथ शुभारंभ किया गया था। आईपीपीबी ने 1.36 लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया और लगभग 1.89 लाख डाकियों व ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ घरों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया है।

आईपीपीबी के शुभारंभ के बाद से इसमें 82 करोड़ के कुल वित्तीय लेन-देन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिसमें 1,61,811 करोड़ रुपये के साथ 21,343 करोड़ रुपये के 765 लाख एईपीएस लेन-देन शामिल हैं। 5 करोड़ खातों में से 77 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, 48 प्रतिशत महिला ग्राहक हैं जिनके इन खातों में लगभग 1000 करोड़ रुपये जमा हैं। लगभग 40 लाख महिला ग्राहकों को उनके खातों में 2500 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त हुआ। स्कूली छात्रों के लिए 7.8 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं।

आकांक्षी जिलों में आईपीपीबी ने 19,487 करोड़ रुपये के कुल 602 लाख लेन-देन वाले 95.71 लाख खाते खोले हैं। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में आईपीपीबी द्वारा 67.20 लाख खाते खोले गए हैं, जिसमें कुल 426 लाख के लेन-देन के साथ 13,460 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

प्रस्ताव के तहत शामिल कुल वित्तीय व्यय 820 करोड़ रुपये है। इस निर्णय से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी। लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने; राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने; द्विपक्षीय व्यापार, निवेश व आर्थिक संपर्क में वृद्धि को सक्षम करने; लोगों के बीच परस्पर संपर्क को और मज़बूत करने के लिए सुविधा प्रदान करने; बहुपक्षीय मंचों पर राजनीतिक आउटरीच को अधिक निरंतरता प्रदान करने की अनुमति देने तथा भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। लिथुआनिया में भारतीय मिशन भारतीय समुदाय की बेहतर सहायता करेगा और उनके हितों की रक्षा करेगा।

लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का निर्णय, विकास की हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता व 'सबका साथ सबका विकास' की दिशा में एक अग्रगामी कदम है। भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं व सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ■

देश में प्रतिदिन करीब 20,000 करोड़ रुपये का डिजिटल लेनदेन हो रहा है: नरेन्द्र मोदी

डिजिटल लेन-देन अब दिल्ली या बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रसार सुदूर के गांवों तक हो चुका है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल को कहा कि देश में प्रतिदिन करीब 20,000 करोड़ रुपये का 'डिजिटल लेन-देन' हो रहा है और इससे देश में एक डिजिटल अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ सुविधाएं बढ़ने के अलावा इससे देश में ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है।

आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 88वें संस्करण में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो गली-नुक्कड़ की छोटी-छोटी दुकानों में भी डिजिटल लेन-देन हो रहा है और इससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं देना आसान हो गया है।

उन्होंने दिल्ली की रहने वाली दो बहनों सागरिका और प्रेक्षा के 'कैशलेस डे आउट' के संकल्प का अनुभव साझा किया और देशवासियों से आग्रह किया वह भी इसे अपनाएं। श्री मोदी ने कहा कि घर से यह संकल्प लेकर निकलें कि दिन भर पूरे शहर में घूमेंगे और एक भी पैसे का लेन-देन नकद में नहीं करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल लेन-देन अब दिल्ली या बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रसार सुदूर के गांवों तक हो चुका है। गाजियाबाद की आनंदिता त्रिपाठी का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी यूपीआई से लेन-देन की सुविधा उपलब्ध है। अब तो छोटे-छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन-देन कर रहे हैं।

डिजिटल लेन-देन अब दिल्ली या बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रसार सुदूर के गांवों तक हो चुका है। गाजियाबाद की आनंदिता त्रिपाठी का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी यूपीआई से लेन-देन की सुविधा उपलब्ध है

श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में करीब 20,000 करोड़ रुपये का डिजिटल लेन-देन हर दिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई लेन-देन करीब 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि अब तो देश में फिन-टेक से जुड़े कई नये स्टार्ट-अप भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से डिजिटल लेन-देन और स्टार्ट-अप की इस ताकत से जुड़े अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया, ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें।

देश की अनमोल विरासत से युवाओं को जोड़ रहा प्रधानमंत्री संग्रहालय

श्री मोदी ने हाल में किये गये प्रधानमंत्री संग्रहालय के लोकार्पण का उल्लेख किया और कहा कि इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री संग्रहालय युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय देश की अनमोल विरासत से युवाओं को जोड़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा 'अमृत महोत्सव' अब एक एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और इस कारण युवाओं में देश के इतिहास को जानने को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है।

उन्होंने देशवासियों, खासकर युवाओं में देश के इतिहास के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ रोचक सवाल भी किए और उनसे इसका नमो ऐप या सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर जवाब मांगा। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछे ताकि हमारी नई पीढ़ी में जिज्ञासा बढ़े, वे इनके बारे में और पढ़ें तथा इन्हें देखने जाएं।

श्री मोदी ने उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उल्लेख किया और इसके बारे में गुरुग्राम के रहने वाले सार्थक नाम के युवा के अनुभवों को साझा किया और देशवासियों को बताया कि जब उन्होंने इस संग्रहालय का अवलोकन किया तो कई सारी नयी जानकारियां मिलीं। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास और देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि देश के लिए यह गौरव की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है।

इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री संग्रहालय युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश के अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद संग्रहालयों के महत्व की वजह से अब लोग आगे आ रहे हैं इसके लिए दान भी कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि बहुत से लोग अपनी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को भी संग्रहालयों में दान कर रहे हैं। लोग जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से वह एक सांस्कृतिक पूंजी को पूरे समाज के साथ साझा करते हैं। भारत में भी लोग अब इसके लिए आगे आ रहे हैं।

ऐसे सभी प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बदलते हुए समय के हिसाब से संग्रहालयों में नए तौर-तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और उनके डिजिटलीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने 18 मई को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए युवा वर्ग का आह्वान किया कि वे आने वाली छुट्टियों में अपने दोस्तों की मंडली के साथ किसी न किसी स्थानीय संग्रहालय को जरूर देखने जाएं।

उन्होंने युवाओं से इसके अनुभव भी साझा करने को कहा ताकि इससे दूसरों के मन में भी संग्रहालयों के लेकर एक जिज्ञासा पैदा हो और वे भी उनके बारे में जानने और समझने के लिए योजना बनाएं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने 'परीक्षा पर चर्चा' के दौरान छात्रों में गणित के विषय के डर को लेकर जताई गई चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ऐसा विषय है, जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए।

गणित में भारत का सर्वाधिक शोध व योगदान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। इसकी खोज न होती, तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। कैलकुलस से लेकर कम्प्यूटर्स तक सारे वैज्ञानिक आविष्कार शून्य पर ही तो आधारित हैं।

श्री मोदी ने वैदिक गणित सिखाने वाले कोलकाता के गौरव टेकरीवाल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वैदिक गणित से बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी माता-पिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाएं। श्री मोदी ने कहा कि इससे, उनका विश्वास बढ़ेगा, साथ ही तार्किक क्षमता भी बढ़ेगी। ■

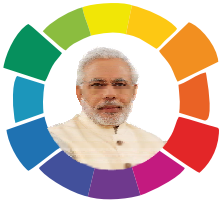

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

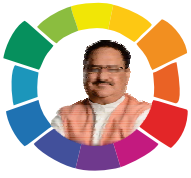

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ में सात नए कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड–19 स्थिति की समीक्षा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बर्लिन (जर्मनी) में औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, साथ में— जर्मनी के चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज़

पेरिस के एलिसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कोपेनहेगन (डेनमार्क) में भारत–डेनमार्क व्यापार मंच कार्यक्रम के दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह